

मोपाल

24 जून 2026
बुधवार

आज का मौसम

35.0 अधिकतम
22.4 न्यूनतम

दोपहर मेट्रो



Page-7

परिसीमन की राजनीति और समाजवादी पार्टी में सैंध का खेल

महिला आरक्षण और परिसीमन भारतीय राजनीति के दो ऐसे मुद्दे बन चुके हैं, जो केवल संवैधानिक संशोधन नहीं बल्कि अगले एक दशक की चुनावी राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों के इर्द-गिर्द आज सत्ता और विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई चल रही है।



समाचार विश्लेषण
राजेश सिसरोठिया

एक बात तो तय है की एनडीए सरकार महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण और लोकसभा की सीट मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मसला यही है को वह पूर्व में पारित इस प्रस्ताव को 2011 जनगणना के आधार पर यह करना

चाहती है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं। इसके पीछे उसके मन में छुपे अंधकारमय भविष्य की आशंका से भरा है। हालांकि हालत अभी भी दुरुस्त नहीं पर उसे नए संविधान संशोधन से और भी बड़े खतरे नजर आ रहे हैं। यह सब आइल्ललाइये कतई नहीं की कांग्रेस के पास एक ठोस वोट बैंक है जिसे उसकी फिक्स डिपॉजिट कहें तो कतई गलत नहीं होगा। इसको बढ़ाने के लिए वह कांग्रेस की विचारधारा दे हटकर सनातनी समाज को बाँटकर और पुष्ट करना चाहती है। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने भी इसकी कोशिश नहीं की। क्योंकि वे सब जानते थे कि जातिगत जनगणना का ब्रिटिश सरकार का फार्मुला हिंदू समाज को बाँटने और हिंदू मुस्लिम खाई को चौड़ा करके राज करने का था। लेकिन अपनी लगातार नाकामियों को ढकने के लिए राहुल गांधी या उनकी काकस मंडली सारे जतन कर रहे हैं।

उनके मानस को समझने की कोशिश करें तो वह खुद कैसे जीते, इस थ्योरी पर उन्हें यकीन नहीं है। उनकी थोसिस अराजकता और अव्यवस्था में देश को धकेलकर विरोधी को पराजित करने वाली है। यह कांग्रेसी सोच नहीं है। यह विदेश से आयातित वामपंथी सोच है, जिसे कांग्रेस ने फ्रेंचाइजी के बतौर ले रखा है। वामपंथ एक विचार है लेकिन उसके पास कोई जनाधार नहीं। कांग्रेस के पास जनाधार है पर वह अपने विचार और विचारधारा को त्याग चुकी है। यानी यह राम मिटाये जोड़ी एक निर्धन एक कोढ़ी वाला बेमेल सा गठजोड़ बन चुका है। अब यह गठजोड़ विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी देशज सोच पर खड़े विचार को पराजित करना चाहता है। अब आप खुद ही सोचिए कि यह कैसे मुमकिन होगा? यह तभी जो सकता है जबकि आपके पास अपने विरोधी के मुकाबले ज्यादा सशक्त विकल्प और प्रकल्प (कार्यक्रम और नीतियाँ) हों? क्या ये है?

बिल्कुल नहीं। अब वापस लौटते हैं एनडीए के उस सपने की तरफ जिसे साकार करने के लिए वह संसद यानी लोकसभा और विधान सभा में दो तिहाई बहुमत की खातिर जमीन समान एक कर रहा है। इसके लिए उसे डीएमके का साथ मिल सकता है और कुछेक छोटे दलों से भी जरूरी आंकड़े को हटा जा सकता है। 'राजनीतिक संकेत बताते हैं कि एनडीए सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन को हर हाल में लागू कराने के पक्ष में दिखाई देती है। अब लौटते हैं उस राजनीतिक रणनीति की ओर, जिसे लेकर सत्ता के गलियारों में सबसे अधिक चर्चा है। एनडीए सरकार का लक्ष्य केवल महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक नहीं बल्कि उसके साथ समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ताकत को सीमित करना भी माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा

सांसदों में से बड़ी संख्या को अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि यह लक्ष्य जितना आसान दिखाई देता है, उतना है नहीं। इनमें लगभग एक दर्जन सांसद ऐसे हैं जो या तो सीधे यादव परिवार से जुड़े हैं या मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सांसदों का दल बदलना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से अत्यंत कठिन माना जाता है। यही कारण है कि भाजपा चाहे जितने बड़े दावे करे, उसे भी इस अभियान की वास्तविक कठिनाइयों का पूरा अनुमान होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों को फिलहाल अंतिम सत्य मान लेना जल्दबाजी होगी। यह वास्तविक राजनीतिक कवायद भी हो सकती है और विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी। आने वाले कुछ सप्ताह तय करेंगे कि यह हकीकत बनती है या केवल एक सियासी शिगूफा साबित होती है।

न्यूज विंडो

दिल्ली में मजदूरों के कैंप में लगी आग, 200 घर जले नई दिल्ली। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके के पास बने मजदूरों के कैंप में आज भीषण आग लग गई। लगभग 200 मजदूरों के अस्थायी आवास जलकर राख हो गए। ये आग सेना भवन के पास लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 20 से अधिक यूनिट ने आग पर काबू पा लिया है। आग से काफी सामान जल गया है। किसी के हाताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए फायर ऑफिसर संदीप दुगल ने कहा, 'यह सेना भवन के पास है। यह मजदूरों के रहने के लिए एक अस्थायी निर्माण है। उनका कैंप यहीं बना हुआ है।

सीएम शुभेंद्रु ने सड़कों के नाम बदलने के लिए बनाई कमेटी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुगलों, पठानों या ब्रिटिश शासकों के नाम पर सड़कें या इलाके नहीं होंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी ने विधानसभा में दी। विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान बोलते हुए सीएम शुभेंद्रु ने सड़कों और इलाकों के नामों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की।

देश की सबसे बड़ी निजी गोल्ड माइन का उद्घाटन

अमरावती। आंध्र प्रदेश के जॉनागिरी में 405 करोड़ रुपये की लागत से बने देश के सबसे बड़े निजी गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे। परियोजना से पहले साल 400 किलोग्राम और बाद में सालाना 2 टन तक सोना उत्पादन होने की उम्मीद है। इससे 700 लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की रॉयल्टी प्राप्त होगी। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले का जॉनागिरी इलाका अब देश के गोल्ड मैप पर अपनी खास पहचान बनाने जा रहा है। इस परियोजना को जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है।

पिता ने पत्नी और 3 मासूम बच्चों को नहर में फेंका

चंपारण। बिहार के पश्चिम चंपारण में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। कुमानबाग थाना क्षेत्र के भंगहा गांव में रहने वाले रामबाबू यादव पर अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों को नहर में फेंकने का आरोप लगा है। इस दर्दनाक घटना में तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि पत्नी ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। भंगहा गांव निवासी लोरिक यादव के बेटे रामबाबू यादव का रात अपनी पत्नी ललिता देवी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

आज का कार्टून



पुणे के लोहागढ़ किले का चर्चित हत्याकांड... चेतन से प्यार और केतन से सगाई, सिया ने की बेवफाई

जून की गर्मी में हुडी पहने देखकर पुलिस को शक हुआ, सीसीटीवी ने खोली हत्या की पोल

पुणे, एजेंसी

शहर के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग के दौरान हुई घटना जिसे शुरू में एक हादसा माना जा रहा था, वह हत्या का मामला निकला। ऐसा तब हुआ जब पुलिस का ध्यान एक अजीब बात पर गया जून के महीने में, जब तापमान 33 डिग्री था, तब एक आदमी ने हुडी पहनी हुई थी और तेज-तेज कदमों से चलता जा रहा था। उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। किले के टिकट काउंटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में वह हुडी पहने आदमी कैद हो गया। बाद में उसकी पहचान चेतन चौधरी के तौर पर हुई, जो सिया का प्रेमी था और उसके साथ मिलकर केतन की मंगेतर सिया ने उसे मौत दे दी।

किले के टिकट काउंटर के पास लगे सीसीटीवी के फुटेज में चेतन 18 जून को पुणे के 26 साल के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल और उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल का पीछा करते हुए दिखाई दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद केतन की मौत हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिए उस आदमी की सदृश्य हरकतें, अपना चेहरा छिपाना और उसके अजीब कपड़े देखकर पुलिस को केतन की मौत के मामले की फिर से जांच करने का ख्याल आया, जिसे शुरू में गलती से हुडी मौत का मामला माना गया था। जब पुलिस ने इस मौत की घटना की जांच की, तो पता चला कि केतन की मौत वाले दिन चेतन अपना फोन अपनी दुकान में ही छोड़ गया था।



मंगेतर के साथ रोमांटिक वीडियो पोस्ट

पुणे में मंगेतर की हत्या करने वाली सिया गोयल (20) ने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन अग्रवाल के साथ कई रोमांटिक पोस्ट किए थे। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, तो कभी डांस और गले मिलने के वीडियो। दोनों की नवंबर में होने वाली भव्य शादी की तैयारियां भी सोशल मीडिया पोस्ट का हिस्सा थीं। फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक कैक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था- मेरे दिल को उसका घर मिले एक महीना पूरा हुआ। उसने और केतन को टैग भी किया था। मई में उसने केतन के फूल देने वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा- उसने 'पसंद है तुम्हें' वाली बात को बहुत सीरियसली ले ले लिया। बैकग्राउंड में 'पसंद है तुम्हें' गाना बज रहा था। एक अन्य स्टोरी में उसने केतन की तस्वीर को 'देट स्पाइल' कैप्शन के साथ शेयर किया था।

चेतन हुडी से घुपा रहा था चेहरा

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी में देख रहे उस आदमी ने शॉर्ट्स और हुडी पहनी हुई थी। हुडी का अगला हिस्सा इतना नीचे खींचा हुआ था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही, उस आदमी ने हुडी के ऊपर हेडसेट भी पहना हुआ था। पुलिस ने जब घटना के समय मौसम की स्थिति की जांच की तो पता चला कि 18 जून को उस समय का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, जिससे हैरानी हुई कि इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा। ऐसे मौसम में किसी व्यक्ति का अपना चेहरा ढके हुए होना मौत नहीं हत्या के लिए एक अहम सुराग बन गया। वहीं सिया के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि चेतन के साथ उसकी बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। दोनों के बीच लंबे समय तक हजारों कॉल हुए थे, जिनमें कई बातचीत घंटों तक चली थीं। तकनीकी जांच से दोनों के बीच करीबी संबंध का पता चला और एक सोची-समझी साजिश की जानकारी मिली। इसके बाद जब पुलिस ने उनकी तस्वीरें और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की तो संदेह हुआ कि सिया चेतन से प्यार करती थी और केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी।

नीरव मोदी को झटका

फ्रॉड केस में सौ करोड़ भुगतान करना होगा

नई दिल्ली, एजेंसी
भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नीरव मोदी को बैंक फ्रॉड मामले में 100 करोड़ से अधिक भुगतान करना होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश साइमन टिककर ने नीरव को व्यक्तिगत गारंटी के तहत देनदार ठहराया। खबरों के मुताबिक नीरव पर 4.1 मिलियन डॉलर (लगभग 38.9 करोड़ रुपये) की मूल राशि बकाया है। बैंक इसमें निर्धारित ब्याज भी जोड़ेगा। रिपोर्टर के मुताबिक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नीरव या उनके वकील ने अपने बचाव में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। नीरव ने तर्क दिया था कि गारंटी लागू करने योग्य नहीं थी। उसने बैंक से वैध मांगें कभी प्राप्त नहीं की थीं। बैंक ऑफ इंडिया ने फायरस्टर डायमंड एफजेडई को दुबई में कर्ज दिया था। नीरव ने 3 अगस्त 2013 को इसकी व्यक्तिगत गारंटी दी थी।

मुंबई में बारिश से सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भरा पानी अंधेरी सब-वे बंद, मध्यप्रदेश में प्री-मानसून बारिश जारी

मुंबई/भोपाल/जयपुर/पटना, एजेंसी

मानसून की मुंबई में एंट्री के पहले 24 घंटे में ही लोगों की परेशानी बढ़ गई। मंगलवार सुबह 8 बजे से आज सुबह 7 बजे तक दो मलवणी फायर स्टेशन में 334एमएम, एफ/साउथ वार्ड में 328एमएम बारिश हुई है। इसके अलावा 27 इलाकों में 200 एमएम से 300 एमएम के बीच बारिश हुई।

बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में भारी जलभरोव हो गया। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया और सिविक अधिकारियों द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवाजाही पर रोक लगाने के कारण यात्रियों को ट्रैफिक में रुकावटों का सामना करना पड़ा। मुंबई में अंधेरी सब-वे में पानी भर गया। इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया है। विक्रोली वेस्ट में रिहायशी इमारत के पास बनी रिटेंनिंग



मुंबई में तेज आंधी से पेड़ उखड़े। हाईकोर्ट कैंपस में एक पेड़ उखड़कर वाहनों पर गिरा।

वॉल गिर गई। मुंबई और पालघर में बारिश का रेड, राणे-रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट है। इधर, देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री-मानसून बारिश जारी है। मप्र के 17 जिलों

में मंगलवार को प्री-मानसून बारिश रही। बिहार में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में 1 से 21 जून तक सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हुई। इस दौरान सामान्य बारिश 28एमएम होती है, जबकि इस सीजन में अब तक 39.3mm औसत बारिश हो चुकी है।

पीस डील पर यूई को मनाने पहुंचे रूबियो अमेरिकी सीनेट में ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास, तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकें

तेहरान/वाशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। 50-48 वोटों से मंजूरी हुए इस प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।

1973 के वॉर पॉवर्स एक्ट के बाद यह पहला मौका है, जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति से युद्ध जैसी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है। वॉटिंग के दौरान चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे ट्रम्प की पार्टी के भीतर बढ़ती बागवत भी सामने आई।

राहत.. स्टेट ऑफ होर्मुज से निकले 11 भारतीय जहाज

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम करने के समझौते के बाद भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कच्चे तेल, गैस और उर्वरक लेकर भारत आ रहे 11 व्यापारिक जहाज स्टेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुके हैं। साथ ही, दो अन्य भारतीय जहाज भी भारत से फारस की खाड़ी की ओर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों दिशाओं से जहाजों की यह आवाजाही स्टेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों के हटने का संकेत देती है।

मेट्रो एंकर

अदालतों के सामने जनता का भरोसा बनाए रखने की चुनौती

नई दिल्ली, एजेंसी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि आज के समय में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालत पर आम जनता का भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने साफ किया कि इस चुनौती का एकमात्र समाधान जजों का ज्ञान, उनकी ईमानदारी और निष्पक्ष व तेजी से न्याय देने की उनकी प्रतिबद्धता है।
मॉस्को में भारतीय सुप्रीम कोर्ट और रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बातचीत की शुरुआत करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ये बातें कहीं। इस मौके पर रूस के सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन इगोर क्रानोव भी मौजूद थे।

भारत में तकनीक से बदल रही है अदालतों की तस्वीर

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि भारत में अदालतों को आम लोगों के लिए आसान, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत में अब सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं। जैसे कि मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट। अदालती दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और ऑनलाइन उपलब्धता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई।

अदालतों के मुख्य काम में एआई की कोई भूमिका नहीं होगी...

इस मुद्दे पर सूर्यकांत ने बताया कि भारतीय न्यायपालिका में कानूनी रिसर्च और अदालती फैसलों का 16 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एआई की मदद ली जा रही है। हालांकि, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विवादों का फैसला करने जैसे अदालतों के मुख्य काम में एआई की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय देना हमेशा एक मानवीय प्रयास है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए। एआई केवल जानकारी जुटाने, अनुवाद करने कामों को आसान बनाने में जजों की मदद कर सकता है, फैसला नहीं सुना सकता।

तकनीक सिर्फ मदद के लिए

सीजेआई सूर्यकांत ने बदलते दौर में तकनीक और एआई की भूमिका पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि तकनीक अदालतों का दायरा और उनकी पहुंच को बढ़ा सकती है, लेकिन न्याय की गुणवत्ता अंत में जजों की समझदारी, ईमानदारी और उनके समर्पण से ही तय होती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तकनीक न्याय देने में मदद तो कर सकती है, लेकिन यह कभी भी न्यायिक मूल्यों और जजों के फैसलों की जगह नहीं ले सकती।





पुतलीघर बस स्टैंड की बढहाल सड़कें बर्नी यात्रियों की परेशानी का सबब



भोपाल। पुराने शहर स्थित पुतलीघर बस स्टैंड की हालत लगातार खराब होती जा रही है। बरसात शुरू होते ही बस स्टैंड परिसर और आसपास की सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिससे यात्रियों, बस चालकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से उपेक्षा का शिकार यह बस स्टैंड अब यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र कम और मुसीबत का केंद्र अधिक बनता जा रहा है। बारिश के पानी से गड्ढों में जलभराव होने के कारण सड़क और गड्ढों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बसों के साथ-साथ दोपहिया वाहन चालक भी दुर्घटना की आशंका के बीच सफर करने को मजबूर हैं। बस स्टैंड पर आने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा

परेशान हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि बस में चढ़ने और उतरने के दौरान कीचड़ और पानी से भरे गड्ढों के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कई बार संबंधित विभाग और नगर निगम को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। जगह-जगह फैला कीचड़ और जलभराव न केवल यातायात को प्रभावित कर रहा है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी बढ़ावा दे रहा है। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुतलीघर बस स्टैंड की सड़कों का तत्काल मरम्मत कार्य कराया जाए।

आर्थिक संकट गहराने से कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने विनियामक समिति को भेजा प्रस्ताव

निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में आधी से ज्यादा सीटें खाली, शुल्क घटाने की मांग

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

प्रदेश के निजी कॉलेजों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और सस्ती होने की संभावना है। कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने शुल्क विनियामक समिति एफआरसी को अपने न्यूनतम शुल्क में कटौती का प्रस्ताव भेजा है। उनकी मांग है कि उनके यहां शिक्षण शुल्क 35 हजार रुपये सालाना कर दिया जाए। इंजीनियरिंग कॉलेजों की इस मांग पर मध्यप्रदेश की शुल्क विनियामक समिति का निर्णय बेहद अहम होगा। इसकी मंजूरी मिलती है, तो यह निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पूरे तंत्र को प्रभावित करेगा। बताया जाता है कि कई निजी संस्थान विद्यार्थियों की कमी से जूझ रहे हैं। पिछले एक दशक में 58 कॉलेज बंद हो चुके हैं। इस बीच केवल एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। पिछले वर्षों में इन कॉलेजों की औसत 45 से 55 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हो पाए। वहीं, सरकारी कॉलेजों में 80 से 90 प्रतिशत सीटें भर जाती हैं। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों की तुलना में यहां इंजीनियरिंग का शुल्क कम है। इस कारण यहां पर दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी प्रवेश लेते हैं। कुछ कॉलेज विवि. में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए वे काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं।

यूजी-पीजी : एक लाख 29 हजार विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश अब प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया कॉलेज स्तरीय काउंसिलिंग

उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज स्तरीय काउंसिलिंग सीएलसी राउंड के लिए महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस चरण में प्रदेशभर के एक लाख 29 हजार 265 विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। इसमें स्नातक में सबसे ज्यादा आवंटन हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया कॉलेज राउंड सीएलसी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार पहले दो चरणों के राउंड में आवंटित विद्यार्थियों में 94 हजार 703 स्नातक और 34 हजार 562 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर यह आवंटन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 जून तक अनिवार्य रूप से प्रवेश शुल्क जमा करें। निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा नहीं करने पर आवंटित सीट प्रभावित हो सकती है।

ई-प्रवेश पोर्टल पर रखें नजर : विभाग ने विद्यार्थियों से कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी सभी अपडेट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य आवश्यक निर्देशों के लिए ई-प्रवेश पोर्टल का नियमित अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वे वंचित न रहें। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के इस चरण से एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिला है।

बीएड और एमएड की काउंसिलिंग शुरू : बीएड और एमएड के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद 25 जून को मेरिट सूची और 29 जून को सीट आवंटन जारी होगा।



एलएनसीटी ग्रुप के टिकानों पर ईडी की कार्रवाई 200 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की पड़ताल

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी भोपाल के शैक्षणिक ग्रुप एलएनसीटी से जुड़े टिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईओडब्ल्यूए के एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने मामले में जांच शुरू की है। मंगलवार को ईडी ने एलएनसीटी ग्रुप के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर जांच शुरू की है। बता दें छात्रों की फीस, स्कॉलरशिप और शिक्षा लोन को निजी कंपनियों को डायवर्ट कर हेराफेरी करने का आरोप है। ईडी ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्रकरण के बाद मामले को अपने जांच के दायरे में लिया है। आरोप है कि संस्थान ने छात्रों से बस फीस, स्कॉलरशिप वसूला और शिक्षा लोन भी लिया, लेकिन इस राशि का उपयोग शिक्षण संस्थान में लाने के बजाए ग्रुप के संचालक परिवार की निजी कंपनियों में उपयोग किया गया। 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का अनुमान लगाया गया है। इस मामले में ईओडब्ल्यूए द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था। अब उसी के आधार पर ईडी ने अक्टूबर 2025 में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। यह पूरा

छात्रों की फीस, स्कॉलरशिप और शिक्षा लोन को निजी कंपनियों को डायवर्ट कर हेराफेरी करने का आरोप



मामला ग्रुप के प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में स्थित संस्थानों से भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि उन जगहों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। भोपाल में ईडी एलएनसीटी ग्रुप के वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों और संबंधित संस्थाओं के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियों की ओर से आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

एजुकेशन लोन के दुरुपयोग के आरोप

जांच में यह आरोप भी शामिल है कि शिक्षा और संस्थागत गतिविधियों के लिए लिए गए बड़े बैंक लोन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों में किया गया। आरोप है कि लोन का इस्तेमाल निजी संपत्तियां खरीदने और परिवार से जुड़े हितों के लिए किया गया। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है।

कुख्यात बदमाश अरशद बब्बा के गुर्गों ने मांगी रंगदारी

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

हनुमानगंज में कुख्यात बदमाश अरशद बब्बा के गिरोह से जुड़े लोगों ने सड़क पर आतंक मचाया। बदमाश महंगी थार चलाने के लिए पैसा होते हुए रंगदारी मांग रहे थे। आरोपियों में शामिल एक बदमाश थार के बोनट में सवार हो गया। जिसको लेकर पीड़ित जान बचाने भागा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार अरशद बब्बा फिलहाल जेल में हैं। उसे कुछ दिन पहले ही शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने दबोचा है। उसके साथी सलमान, रहमान उर्फ घोड़ा, राशिद समेत आठ-दस आरोपी काजिकेप में स्थित सलीम चाय की दुकान में खड़े थे। यहां 24 वर्षीय अददान खान थार लेकर पहुंचा। वह विदिशा जिले के सिरोंज का रहने वाला है। वह बाफना कॉलोनी में रहने वाली बुआ के घर आया हुआ है। यहां रिश्तेदारी में शादी है। अददान खान से उसके चचेरे भाई के बारे में पूछा। इसके बाद वह उससे 15 हजार रुपए मांगने लगे। उसने इंकार किया तो आरोपी बोले इतनी महंगी कार चलाने के लिए पैसा है और वह मदद मांग रहे हैं तो होशियारी दिखा रहा है। इसके बाद आरोपियों ने चाकू निकाला और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक आरोपी उसकी थार की बोनट में भी चढ़ गया। अददान खान बचाने वाहन से भागा।

श्री सिद्ध चक्र विधान श्रद्धा भक्ति आस्था का संगम... उत्साह से सरोबार इंट इंद्राणी डूबे भक्ति में

भोपाल। श्री महावीर जैन मंदिर वर्धमान नगर दाता कॉलोनी में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ उत्साह से सरोबार भक्ति रस में डूबे श्रद्धालु भगवान सिद्ध की आराधना में भगवान जिनेंद्र का अभिषेक शांतिधारा के साथ जप तप साधना में लीन है। प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया हाथों में अष्ट द्रव्य लेकर 64 रिद्धि अर्थ अर्पित किए जिनालय में आकर्षक मंडल सजा है। अनुष्ठान में श्रद्धालु प्रभु की आराधना में लीन है। प्रतिष्ठाचार्य प्रकाश छोट्ट भैया के निर्देशन में धार्मिक अनुष्ठान हुए। प्रभु की भक्ति में भजन के साथ आराधना की गई। प्रमुख पात्र सो धर्म इंद्र नवीन सविता दीक्षा प्रतीक श्री पाल मेना सुंदरी श्रीमती मालती दिशा, चंदना ध्वजारोहण करती सुनीता प्रमोद कुबेर, मंडल वीरेंद्र सुनीता, विजय, विनोद, अनिल, महावीर,तनु जैन ने मंडल पर श्रीफल अर्पित कर सभी के मंगल मय जीवन की कामना की।



अब स्कूल जाने के लिए बच्चों को मिलेगी अच्छी सड़क

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

नारियलखेड़ा के शारदा नगर स्थित कमल सिंह शासकीय माध्यमिक स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को अब कीचड़ से होकर नहीं आना होगा। वार्ड 12 के पार्षद देवेन्द्र भार्गव की पहल से बच्चों के साथ रहवासियों को अच्छी मजबूत सीमेंट की सड़क मिलेगी। इस सड़क का भूमिपूजन पार्षद भार्गव ने शाला परिसर के सामने किया। इस मौके पर शाला के शिक्षक- शिक्षिकाएं और बच्चे उपस्थित रहे। इससे पहले शाला परिवार ने भार्गव का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। 25 साल बाद हो रहा विकास कार्य पार्षद भार्गव ने बताया कि नारियलखेड़ा वार्ड के शारदा नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, निशातपुरा, नारियलखेड़ा, प्रेमनगर, गणेश नगर



आदि में करीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड, नालियां, शारदा नगर में 20 लाख गैलन क्षमती पानी टंकी, नारियलखेड़ा में प्रवेश द्वार, मुख्य मार्ग का डामरीकरण आदि कार्य कराए जा रहे हैं। दिसंबर तक ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। नारियलखेड़ा चौराहे का सौंदर्यकरण भी किया जा रहा है। बता दें कि नारियलखेड़ा इलाके की एक दर्जन बस्तियों में 25 साल बाद दोबारा सड़कें- नालियां बनाई जा रही है।

वेस्टर्न बायपास परियोजना

फेंसिंग खड़ी करने को लेकर विवाद



भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मंडीदीप से कोलार होकर सीहोर के फंदा तक जाने वाली प्रस्तावित वेस्टर्न बायपास परियोजना को प्रशासनिक स्तर पर बड़ी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद सामने गया है। इसमें केरवा बीट क्षेत्र आ रहा है, जिसमें वन विभाग ने करीब साढ़े चार किलोमीटर तक लगभग 13 फीट ऊंची फेंसिंग खड़ी की है। विवाद इस बात को लेकर है कि जिस भूमि पर यह फेंसिंग लगाई गई है, वह फिलहाल राजस्व विभाग की है। इस फेंसिंग का विरोध करने वाले बीट क्षेत्र के निवासी कार प्रभावित पक्ष न्यायालय की शरण में जा चुके हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली एम्पावर्ड कमिटी ने 35.61 किमी लंबे वेस्टर्न बायपास को मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव अगले माह कैबिनेट के समक्ष जाएगा। अब इस प्रस्तावित मार्ग के समीप केरवा बीट क्षेत्र में वन विभाग को खड़ी फेंसिंग को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसमें वनविभाग जो फेंसिंग बना रहा है, उसमें चार लोगों की जमीन आ रही है। इन लोगों ने विरोध जताया है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर पहले से मौजूद निजी

सुरक्षा दीवारों का उपयोग करते हुए नई फेंसिंग खड़ी कर दी गई, जिससे भूमि स्वामित्व और अधिकारों को लेकर सवाल पैदा हो गए हैं। मंडीदीप से कोलार होकर सीहोर के फंदा तक जाने वाली प्रस्तावित भोपाल वेस्टर्न बायपास परियोजना लगभग 2900-3225 करोड़ की लागत से बनेगी। इससे लगभग 35 से 41 किलोमीटर लंबा यह फोर-लेन बायपास भारी वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना सीधे जबलपुर/नर्मदापुरम से इंदौर की ओर निकलेगा। यह नया मार्ग मंडीदीप औबेदुल्लागंज रोड से शुरू होकर कोलार, रातीबड़, और खजूरी होते हुए इंदौर मार्ग पर फंदा कला में जाकर मिलेगा।

वहीं केरवा वन बीट के रेंजर शिवपाल पिपरादे का तर्क है कि यह कदम वन्य प्राणियों और स्थानीय रहवासियों दोनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। पिपरादे ने कहा कि राजस्व भूमि के वन विभाग को हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। सुरक्षा मामलों में केवल निजी दीवारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। वहीं डीएफओ लोकप्रिय भारती ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने रेंजर कार्यालय से तथ्यात्मक जानकारी तलब की है।

मेट्रो एंकर

मशीनों से बनेगा हाइजैनिक भोजन, गैस सिलेंडर का नहीं होगा इस्तेमाल

सांदापनि विद्यालयों में अब 'इलेक्ट्रिक किचन' में बनेगा मध्याह्न भोजन

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मध्य प्रदेश के 370 सांदापनि स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) अब गैस सिलेंडर की जगह आधुनिक इलेक्ट्रिक किचन में तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को साफ, सुरक्षित और पोषिक भोजन उपलब्ध कराना है।

इस नई व्यवस्था का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की इकाई प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण संस्था करेगी। इसके लिए स्कूलों में आधुनिक मशीनों और इलेक्ट्रिक किचन लगाए जा रहे हैं। इन किचनों में एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों का भोजन तैयार किया जा सकेगा। भोजन बनाने समय



स्वच्छता और हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता का भोजन मिल सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से मिड-डे मील की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों के स्वास्थ्य को भी

लाभ मिलेगा। इसके लिए स्कूलों में अत्याधुनिक मशीनों और इलेक्ट्रिक किचन सेटअप तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हजारों बच्चों का भोजन एक साथ और बेहद सुरक्षित माहौल में तैयार हो सकेगा। बता दें कि प्रदेश से सांदापनि स्कूल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में अब बच्चों का लंच बनते समय पूरी तरह हाइजीन और स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। इस नई व्यवस्था में भोजन पकाने के लिए पारंपरिक गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पूरा भोजन बिजली से चलने वाले अत्याधुनिक उपकरणों इलेक्ट्रिक किचन में तैयार होगा, जिससे हादसे

की गुंजाइश न के बराबर होगी। इस किचन में आटा गूंथने, रोटियां बनाने, सब्जी काटने और खाना पकाने तक का अधिकतम काम मशीनों के जरिए होगा। इससे खाने की शुद्धता और हाइजीन का स्तर बेहद ऊंचा रहेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 27 नए सांदापनि स्कूल में तीन किमी रेंज में स्थित प्रदेश के 264 प्राइमरी और मीडिल स्कूलों का विलय कर दिया है। इससे लगभग 25 हजार बच्चे सांदापनि में मर्ज हो चुके हैं। ऐसे में छोटे स्कूलों के जुड़ने से यहां छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। चूंकि कक्षा 1 से 8 के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है।



आदिरंग महोत्सव का भव्य समापन: सीएम यादव बोले

जनजातीय कला को मिलेगा वैश्विक मंच सिकल सेल नियंत्रण में भी मप्र अग्रणी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पांच दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई आकर्षक शिल्प कृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों से संवाद कर उनके नवाचारों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 से प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह बीमारी कई पीढ़ियों को प्रभावित करती है, इसलिए समय पर स्क्रीनिंग और उपचार बेहद आवश्यक है।

जनजातीय शिल्प को मिल रही नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिरंग महोत्सव ने जनजातीय कलाकारों की प्रतिभा को नया मंच दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और शिल्प का उंका अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) द्वारा पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन और बाजार की जरूरतों के अनुरूप प्रस्तुत करने का प्रयास सहाय्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर में लोक संस्कृति और पारंपरिक कला को बढ़ावा देकर विकास के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश प्रवास को भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। सीएम ने कहा कि 24 जून वीरगंगा रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने गौडवानी की अस्मिता और स्वाभिमान को रक्षा के लिए मुगल सत्ता के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े और अद्वितीय साहस का परिचय दिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जनजातीय वीरों और वीरगंगाओं की गौरवशाली धरती है, जिनकी प्रेरणा आज भी समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है।

कला से बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिरंग महोत्सव केवल कला प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजातीय कलाकारों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने का माध्यम भी बनेगा। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति के संरक्षण के साथ कलाकारों को बाजार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जनजातीय समाज भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सहयोग से आयोजित आदिरंग महोत्सव ने मध्य प्रदेश की पारंपरिक जनजातीय कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित कर उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

एनआईडी ने जोड़ी परंपरा और आधुनिक डिजाइन

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की निदेशक डॉ. विद्या राकेश ने कहा कि आदिरंग केवल शिल्पकार महोत्सव नहीं, बल्कि डिजाइन, संस्कृति, समुदाय और सशक्तिकरण को जोड़ने वाली पहल है। उन्होंने बताया कि एनआईडी ने जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से बैगा, गोंड, भील सहित विभिन्न जनजातीय समुदायों के बीच डिजाइन विकास कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनमें कलाकारों को उत्पाद विकास, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि उनकी कला आधुनिक बाजार से जुड़ सके। साथ ही जनजातीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण कर उसके संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।

समिति को साढ़े नौ लाख सुझाव मिले यूसीसी के समर्थन में 71 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले आम नागरिकों से सुझाव लिए गए हैं। राज्य स्तरीय समिति को मंगलवार तक करीब साढ़े नौ लाख सुझाव मिले हैं। इनमें मुस्लिम पुरुषों में केवल 38 प्रतिशत ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि 15 हजार मुस्लिम महिलाओं में से 10.5 हजार यानी 71 प्रतिशत ने यूसीसी के पक्ष में सुझाव दिया है। सुझावों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज की बढ़ी संख्या में महिलाएं कानूनी सुधारों, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में हैं।

सार्वजनिक परामर्श के दौरान समिति को व्यक्तिगत श्रेणी में 9.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। इनमें 8.9 लाख यानी 93 प्रतिशत लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। आम जनता के अलावा विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली करीब 2 हजार संस्थाओं ने भी संगठनात्मक और तकनीकी सुझाव दिए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

इस परामर्श प्रक्रिया में लैंगिक संतुलन भी देखने को मिला। कुल सुझावों में महिलाओं के 4 लाख और पुरुषों के 5.5 लाख सुझाव शामिल थे। इसके साथ ही 100 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने भी अपनी राय दर्ज कराई।

यूसीसी को हिंदू समाज का एकतरफा समर्थन

धार्मिक और लैंगिक आधार पर देखें तो हिंदू समुदाय में यूसीसी को सबसे व्यापक समर्थन मिला है। 5.2 लाख हिंदू पुरुषों में से 4.9 लाख (95 प्रतिशत) और 3.7 लाख हिंदू महिलाओं में से 3.6 लाख (97 प्रतिशत) ने इसके पक्ष में रजामंदी दी है। सभी धर्मों की कुल 4 लाख महिलाओं में से 3.8 लाख यानी 95% महिलाएं यूसीसी के साथ हैं।

मुस्लिम महिलाओं-पुरुषों की राय का बड़ा अंतर

रिपोर्ट का सबसे प्रमुख पहलू मुस्लिम समुदाय में पुरुषों और महिलाओं की राय में अंतर का दिखा। मुस्लिम वर्ग से कुल 44 हजार सुझाव मिले थे, जिनमें 29 हजार पुरुष और 15 हजार महिलाएं शामिल थीं। 29 हजार मुस्लिम पुरुषों में से 11 हजार (38 प्रतिशत) ने इसका समर्थन किया, जबकि महिलाओं ने 71 प्रतिशत बहुमत के साथ इसका समर्थन किया है। जानकारों का मानना है कि पौरुष संघर्ष में बराबर हक, बहुविवाह पर रोक, तीन तलाक की समाप्ति और गुजारा भत्ता जैसे मुद्दों पर कानूनी संरक्षण की अपेक्षा के कारण मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी को बड़ा समर्थन दिया है।

प्रदेश में आधार सेवा अधोसंरचना का हुआ विस्तार, 10 जिलों में संचालन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा मध्य प्रदेश में आधार सेवाओं को नागरिकों तक अधिक सुगमता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ पहुंचाने के लिए आधार सेवा अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इस पहल से प्रदेश के नागरिकों को आधार नामांकन एवं अद्यतन संबंधी सेवाएं अपने निकट ही उपलब्ध हो सकेंगी। वर्तमान में यूआईडीएआई द्वारा संचालित आधार

सेवा केंद्र (एएसके) प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, विदिशा एवं भिण्ड में संचालित हैं। ग्वालियर और शिवपुरी में मंगलवार से आधार सेवा केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार प्रदेश के 10 जिलों में आधार सेवा केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। आधार केंद्रों पर नागरिकों को आधार नामांकन, डेमोग्राफिक एवं बायोमेट्रिक अपडेट सहित विभिन्न आधार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

अब दिल्ली-मुंबई में भी मान्य होगी जया आरोग्य अस्पताल की जांच रिपोर्ट,

ग्वालियर। जया आरोग्य अस्पताल की जांच रिपोर्ट अब दिल्ली-मुंबई में भी मान्य होगी। ऐसा अस्पताल की लैब को एनएबीएल मान्यता मिलने से संभव हुआ है। इसके लिए 25 अप्रैल को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (इडब्ल्यू) की चार सदस्यीय टीम ने अस्पताल पहुंचकर लैब की व्यवस्थाओं का बारीकी से मुआयना किया था। टीम ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी थी। इसके बाद एनएबीएल ने जया आरोग्य अस्पताल प्रबंधन को प्रमाण पत्र जारी किया। यह प्रमाण पत्र 14 जून 2030 तक मान्य रहेगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली, इंदौर और चेन्नई से आए विशेषज्ञों ने माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विभागों में पहुंचकर यह देखा था कि मरीजों के सैंपल किस तरह लिए जा रहे हैं और उनकी टेस्टिंग के मानक क्या हैं। एनएबीएल के मानकों पर खरा उतरने पर जेएच को यह प्रमाण पत्र मिला। निदेशक दल में दिल्ली से डॉ. अनिता बबर, इंदौर से डॉ. शशि कपूर व डॉ. राजीव लालूके और चेन्नई से डॉ. के. बालन शामिल थे। जेएच अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना ने बताया कि इस प्रमाणन के तहत प्रयोगशाला को आईएसओ मानक के अनुसार मेडिकल परीक्षण के लिए गुणवत्ता और क्षमता में मान्यता दी गई है।

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन

सरकार को मिला अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ करने का अधिकार

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वाले आम लोगों और निवेशकों को भविष्य में बड़ी राहत देने की जमीनी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1% मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब राज्य सरकार के पास यह कानूनी अधिकार आ गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली रजिस्ट्रियों पर लगने वाले अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ या कम कर सकेगी।

चूंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चालू नहीं है और मामले में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता थी, इसलिए राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी कर दिया है। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नया नियम 10 जून 2026 से ही पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है।



किन्हें मिल सकता है संभावित फायदा?

भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पक्षे मकान की रजिस्ट्री या गांवों में नए उद्योग या स्टार्टअप लगाने वाले उद्यमियों को जमीन खरीदते वक्त टैक्स में राहत दी जा सकती है। हालांकि ये सरकार की नीति और मंशा पर निर्भर करेगा कि वह किस वर्ग या स्थान के लोगों को छूट देना चाहती है।

क्या हुआ है बदलाव?

मूल अधिनियम की धारा 75 में संशोधन करते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत लगने वाले नियमित शुल्क के अलावा, धारा 75 के अंतर्गत जो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूला जाता था, सरकार अब नोटिफिकेशन जारी कर किसी भी कानूनी दस्तावेज या विलेख को उस अतिरिक्त शुल्क से छूट दे सकेगी। मान लीजिए किसी जमीन के रजिस्ट्री दस्तावेज पर 1 लाख रुपये सामान्य स्टाम्प ड्यूटी लगती है और 10 हजार रुपये अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी लगती है। यदि सरकार संबंधित श्रेणी के दस्तावेजों को छूट देने की अधिसूचना जारी कर दे, तो 10 हजार रुपये की अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।

प्रदेश में स्मार्ट मीटर से 20 प्रतिशत तक की छूट

भोपाल में 4.50 लाख उपभोक्ताओं को मिली 3.68 करोड़ रु.की टीओडी रिबेट

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मई 2026 तक भोपाल के पांच बिजली वितरण संभागों में कुल 6.17 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 4.50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम आफ डे (टीओडी) योजना का लाभ भी मिल रहा है। मई माह में ही उपभोक्ताओं को 3.68.23 लाख रुपये यानी करीब 3.68 करोड़ रुपये की रिबेट दी गई।

नर्सिंग घोटाला: सीबीआई जांच में फेल 451 कॉलेजों के छात्रों का भविष्य अधर में; परीक्षा के बाद भी रिजल्ट पर रोक

भोपाल। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को जीएनएम (तीन वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में 2022-23 में प्रवेश लेने वाले 245 कॉलेजों के 10 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है। काउंसिल से शीघ्र ही परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी की है। ये वे कॉलेज हैं जो सीबीआई की जांच में उपयुक्त मिले थे। वहीं, इसी बैच के

सिटी ईस्ट में सबसे अधिक उपभोक्ताओं को मिला लाभ

आंकड़ों के अनुसार भोपाल सिटी ईस्ट क्षेत्र स्मार्ट मीटर स्थापना और टीओडी रिबेट के मामले में सबसे आगे रहा। यहां कुल 1,80,237 उपभोक्ताओं में से 1,34,901 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मई में सबसे अधिक 109.34 लाख रुपये की टीओडी रिबेट मिली। इसके बाद भोपाल सिटी नार्थ क्षेत्र में 98,291 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। यहां उपभोक्ताओं को 87.39 लाख रुपये की रिबेट का लाभ मिला। भोपाल सिटी साउथ में 84,628 स्मार्ट मीटर स्थापित हैं और यहां 77.21 लाख रुपये की छूट दी गई। भोपाल सिटी वेस्ट क्षेत्र में 72,137 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। यहां उपभोक्ताओं को मई माह में 46 लाख रुपये की टीओडी रिबेट मिली। वहीं ओ एंड एम कोलार क्षेत्र में कुल 60,645 स्मार्ट मीटर स्थापित हैं और यहां उपभोक्ताओं को 48.28 लाख रुपये की रिबेट वितरित की गई। बिजली कंपनी के अनुसार स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली खपत की वास्तविक समय में जानकारी मिल रही है। इससे बिजली उपयोग पर निगरानी आसान हुई है और ऊर्जा बचत को बढ़ावा मिला है।

355 कॉलेज हुए जांच में फेल

बता दें कि मापदंडों के संबंध में नर्सिंग कॉलेजों में फजीवाड़ा सामने आया था। ला स्टूडेंट एसासिशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई से नर्सिंग कॉलेजों की जांच कराई थी। इसमें जिन कॉलेजों में संसाधन निर्धारित मानक के अनुसार मिले थे उन्हें जांच एजेंसी ने उपयुक्त बताया था। 355 कॉलेजों को अनुपयुक्त और 96 को डिफिशिएंट बताया था।

सीएलसी राउंड में 1.29 लाख विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस चरण में प्रदेशभर के 1 लाख 29 हजार 265 विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटन सूची जारी होने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवंटित विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित करनी होगी। सीएलसी राउंड में आवंटित विद्यार्थियों में 94 हजार 703 स्नातक और 34 हजार 562 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। प्रदेश

30 जून तक जमा करनी होगी फीस

उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे 30 जून तक अनिवार्य रूप से प्रवेश शुल्क जमा करें। निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा नहीं करने पर आवंटित सीट प्रभावित हो सकती है। विभाग ने विद्यार्थियों से कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी सभी अपडेट, दस्तावेज सत्यापन और अन्य आवश्यक निर्देशों के लिए ई-प्रवेश पोर्टल का नियमित अवलोकन करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वे वंचित न रहें। प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए चल रही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के इस चरण से एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिला है।

मेट्रो एंकर

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

महाकाल लोक बनने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ दान का प्रवाह भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को रिकॉर्ड 142 करोड़ रुपए की आय हुई है, जिसमें केवल दान मद से ही 78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह बीते छह वर्षों में सबसे अधिक दान है और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 27 करोड़ रुपए ज्यादा है।

मंदिर समिति के अनुसार दान पेटियों से 62 करोड़ रुपए, नगद काउंटर पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मनी ऑर्डर से 1.23 लाख रुपए, ऑनलाइन माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए, अन्नक्षेत्र से 3 करोड़ 38

महाकाल मंदिर को 142 करोड़ रुपए की आय

पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ रुपए अधिक आया दान

दान बढ़ा तो खर्च भी दोगुना हुआ



लाख रुपए तथा गुप्त दान के रूप में 4 करोड़ 65 लाख रुपए प्राप्त हुए। लड्डू की बिक्री 65 करोड़ की-वहीं लड्डू प्रसादी की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय हुई। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने सोने-चांदी के

श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले महाकाल मंदिर का क्षेत्रफल 2.82 हेक्टर था, जो विस्तार के बाद बढ़कर 47 हेक्टर पर हो गया है। वर्तमान में मंदिर समिति के कुल 306 कर्मचारियों का कार्यरत है। इन कर्मचारियों के वेतन के अलावा मंदिर की सुरक्षा, साफ-सफाई, रखरखाव, निर्माण कार्य, पर्व-त्योहारों की व्यवस्थाएं, धर्मशाला, अन्नक्षेत्र, महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान, गोशाला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बड़ी राशि खर्च होती है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि, श्रावण मास, नागपंचमी सहित अन्य प्रमुख पर्व पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी अतिरिक्त व्यय किया जाता है। पहले मंदिर का मासिक खर्च करीब 2.5 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 5 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिमाह हो गया है।

करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी दान किए हैं। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में करीब तीन गुना

हुई है। राम मंदिर में दान को लेकर चल रहे विवाद के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक आशीष पलवड़िया ने बताया कि मंदिर में प्राप्त होने वाले दान के संबंध में पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। मंदिर परिसर में कुल 95 दान पेटियां स्थापित हैं, जिनमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में दान करते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु न्यूआर कोड के माध्यम से भी ऑनलाइन दान कर रहे हैं। हर सप्ताह दान पेटियां खोली जाती हैं। इन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणना कक्ष तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद निरीक्षक, सहायक प्रशासक तथा मंदिर समिति के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दान पेटियां खोली जाती हैं।

दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जो आकार में भले छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका महत्व महाशक्तियों के बराबर होता है। होर्मुज जलडमरूमध्य ऐसी ही एक जगह है। यह केवल समुद्र का एक संकरा रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनों को नियंत्रित करने वाली वह नस है, जिसके जरिए दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था सांस लेती है। आज जब पश्चिम एशिया में तनाव फिर से उभर रहा है, तब यह जलमार्ग एक बार फिर साबित कर रहा है कि भूगोल कभी पुराना नहीं पड़ता। बीते दशकों में यह धारणा मजबूत हुई थी कि वैश्वीकरण ने सीमाओं के

महत्व को कम कर दिया है।

माना जाने लगा था कि व्यापार,

तकनीक और पूंजी का मुक्त प्रवाह दुनिया को परस्पर निर्भरता के ऐसे दौर में ले आया है, जहां किसी एक देश के लिए वैश्विक व्यवस्था को बंधक बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन हाल की घटनाएं इस विश्वास को चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। होर्मुज का संकट बता रहा है कि आधुनिक दुनिया में भी कुछ दरवाजे ऐसे हैं, जिनकी चाबी एक ही हाथ में रहती है। ईरान की स्थिति इसी सच्चाई को रेखांकित करती है। आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबावों

समुद्र की शक्ति

शक्ति से भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जब भी इस मार्ग की सुरक्षा या संचालन पर सवाल उठते हैं, पूरी दुनिया की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। ऊर्जा बाजार बेचैन हो उठते हैं, बीमा कंपनियां सतक हो जाती हैं और कूटनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ जाती है। लेकिन यह कहानी केवल ईरान की नहीं है। यह उस बदलती विश्व व्यवस्था की कहानी भी है, जिसमें सामरिक 'चोक पॉइंट्स' नई शक्ति के केंद्र बनते जा रहे हैं। समुद्री

जलडमरूमध्य, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाएं, सेमीकंडक्टर उत्पादन केंद्र और डिजिटल नेटवर्क—सब धीरे-धीरे ऐसे औजार बन रहे हैं, जिनके माध्यम से देश अपने प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं। विडंबना यह है कि एक निर्भरता से बचने की कोशिश अक्सर दूसरी निर्भरता की ओर ले जाती है। यदि तेल आपूर्ति के जोखिम देशों को नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ धकेलते हैं, तो वे उन तकनीकों और संसाधनों पर निर्भर होंगे जिन पर कुछ चुनिंदा देशों का प्रभुत्व है। यानी दुनिया शायद एक संकट से निकलकर दूसरे प्रकार के संकट की ओर बढ़ रही है।

समान नागरिक संहिता के विमर्श में बाल अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी

डॉ. निवेदिता शर्मा

रसंतकार



भावनात्मक जुड़ाव बना रहना चाहिए। अभिरक्षा का निर्णय कानूनी अधिकारों के आधार तक सीमित न होकर बच्चे की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। पर्याप्त आयु और समझ रखने वाले बच्चों की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। आखिरकार, उनके जीवन से जुड़े निर्णयों में उनकी आवाज क्यों न सुनी जाए?

एक सभ्य समाज बच्चों को उनके जन्म की परिस्थितियों से न पहचानते हुए उनके व्यक्तित्व और अधिकारों से पहचानता है। चाहे बच्चा विवाह से जन्मा हो, लिव-इन रिलेशनशिप से, दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार में आया हो या किसी पूर्व वैध बहुविवाह से उत्पन्न हुआ हो, उसके अधिकार समान होने चाहिए। उत्तराधिकार, शिक्षा, पहचान, भरण-पोषण और संपत्ति के मामलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चों के साथ अन्याय होगा।

विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुत्र और पुत्री को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त हों। संयुक्त परिवार की सहदायिकी संपत्ति में पुत्री को जन्म से वही अधिकार और दायित्व प्राप्त हों जो पुत्र को होते हैं। यह सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। समाज बदल रहा है और पारिवारिक संरचनाएं भी परिवर्तित हो रही हैं, किंतु परिस्थितियां चाहे जो हों, बच्चे के अधिकार कभी कम नहीं हो सकते। यदि किसी लिव-इन रिलेशनशिप से बच्चा जन्म लेता है, तो उसे पूर्ण वैधता, सम्मान और समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जन्म पंजीयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण और उत्तराधिकार में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। यदि ऐसा संबंध समाप्त होता है, तो बच्चे की अभिरक्षा और भरण-पोषण की स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब किसी घर में हिंसा होती है, तो उसके निशान वहां रह रहे बच्चों के मन पर भी पड़ते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर भय, अवसाद, असुरक्षा और व्यवहारिक समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए विवाह-विच्छेद, अलगाव या घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में बच्चों की सुरक्षा का जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बाल कल्याण समिति या बाल संरक्षण इकाइयों को तत्काल जोड़ा जाना जाए, ताकि किसी भी बच्चे को संकट की स्थिति में अकेला न छोड़ा जाए।

हम सभी जानते हैं कि दत्तक ग्रहण किसी बच्चे को परिवार, पहचान और भविष्य देने की प्रक्रिया है, इसलिए यह जरूरी है कि पूरी तरह पारदर्शी, वैधानिक और बाल-केन्द्रित हो। सभी दत्तक ग्रहण प्रक्रियाएं किशोर न्याय अधिनियम और सीएआरए के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित हों तथा अवैध या अनौपचारिक दत्तक ग्रहण पर पूर्ण रोक हो। दत्तक ग्रहण के बाद भी समय-समय पर निगरानी की व्यवस्था हो, ताकि बच्चे का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। अतः समान नागरिक संहिता की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि उसने कितने कानूनों को एकरूप किया, बल्कि इससे मापी जाएगी कि उसने कितने बच्चों को असमानता, उपेक्षा और असुरक्षा से मुक्त किया। मध्यप्रदेश के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि वह ऐसी यूसीसी का निर्माण करे, जिसमें हर निर्णय का केंद्र बच्चा हो, जहां किसी बच्चे के अधिकार उसकी पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक पृष्ठभूमि से निर्धारित न हों और जहां हर बच्चे को यह भरोसा हो कि कानून उसके साथ खड़ा है।

क्योंकि अंततः किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी आने वाली पीढ़ियां होती हैं। यदि हम उनके अधिकारों और सपनों की रक्षा कर सकें, तो वास्तव में हम एक आर्थिक संचालित हों तथा अवैध या अनौपचारिक दत्तक ग्रहण में आगे बढ़ेंगे। यहां यह भी बता दें कि बच्चों के हित में यह निर्णय सिर्फ मद्र तक सीमित नहीं होने चाहिए, हर राज्य में और देश के स्तर पर जब भी इस तरह की पॉलिसी बने, सभी पर यह लागू होना आज समय की आवश्यकता है।

—यह लेखक के अपने विचार हैं।

सबक नहीं ले रही पुलिस, भरत तिवारी एनकाउंटर से फिर कटघरे में

श्रीगोपाल नारसन

वित्तक, पत्रकार



तराखंड में कई वर्ष पूर्व हुए रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी पुलिस कर्मी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने उस घटना से सबक नहीं लिया और हाल ही में बिहार के 28 वर्षीय युवक भरत तिवारी द्वारा हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर देने पर भी पुलिस ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस एनकाउंटर से उपजे जनविरोध को देखकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की घोषणा की है। बिहार में भोजपुर जिले के शाहपुर

थाना क्षेत्र के बेलौटी

गांव के रहने वाले

युवक भरत भूषण

तिवारी को एनकाउंटर

के नाम पर 17 जून को

पुलिस ने मार दिया

था। उसकी पहचान

गांव और आसपास में

एक ऐसे शख्स की रही

है, जो लगातार स्थानीय

मुद्दों और भ्रष्टाचार के

खिलाफ आवाज उठाता था, लेकिन आक्रामक पृष्ठ

के चलते पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी।

ज्वाइन्या क्षेत्र में गंगा कटाव के कारण जो लोग

विस्थापित हो रहे थे, उनके पुनर्विस्थापन के लिए भरत

काफी सक्रियता से काम कर रहा था। युवाओं में

उसकी अच्छी खासी पकड़ भी थी। खुद को क्रांतिकारी

बताने वाला भरत हथियार भी रखता था।

बीती 15 जून को भरत तिवारी ने फेसबुक पर एक

पोस्ट डाली, जिसमें उसने कहा कि देश में क्रांतिकारी

युद्ध की जरूरत है, इस दौरान आरोप है कि उसने

जगदीशपुर एसडीएम को जान से मारने की भी कथित

धमकी दी। जिस वजह से पुलिस उसके घर पहुंची

लेकिन वह नहीं मिला।

भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बीजेपी नेताओं

की तल्ख टिप्पणी ने बिहार सरकार को असहज कर

दिया है। घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे,

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज

सिन्हा, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और मंत्री विजय

सिन्हा ने भी इस एनकाउंटर की निंदा की है।

विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष भी पुलिसिया

एक्शन पर सवाल उठा रहा है।

16 जून को हथियार के साथ भरत की एक

तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जिसको लेकर

पुलिस उसके घर पहुंची, अधिकारियों से बातचीत के

दौरान उसने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया, जिसमें उसने पुलिस-प्रशासन पर एनकाउंटर में उसे मारने की कोशिश का आरोप लगाया, हालांकि बाद में पुलिस ने भरत को मानसिक रूप से विशिष्ट बता कर अपना बचाव किया। जब पुलिस की टीम गांव पहुंची तो उसकी भरत भूषण तिवारी से टन गई। पुलिस का दावा है कि भरत ने उसकी टीम पर हमला कर दिया, बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग करता रहा, हालांकि भरत तिवारी की फायरिंग का कोई वीडियो सामने नहीं आया, ऐसे में आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, कहना किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। लाइव एनकाउंटर से साफ है कि पुलिस ने उस समय भरत का एनकाउंटर किया, जब वह हथियार डाल चुका था। पुलिस की गोलियां लगने के बाद गंभीर



हालत में उसे पहले आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एनकाउंटर के कुछ ही दिनों बाद तल्ख लहजे में बयान दिया, युवक का व्यवहार और हथियार लहराना गलत था लेकिन पुलिस को पहले उसके आभारपूर्ण इतिहास और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए थी मंत्री ने इसकी निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। एनकाउंटर की घटना को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के शब्दों में, प्रशासन के पास स्थिति को संभालने के विकल्प थे लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करना सरकार का लक्ष्य है, मगर किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भी घटना पर चिंता जाहिर की और मुक्तक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जांच रिपोर्ट आने तक अंतिम निष्कर्ष से बचने की सलाह दी है।

—यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अलर्ट

गर्मियों के मौसम में रात का खाना खाने के बाद ज्यादातर लोग मीठे में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। अगर, आप अधिक मात्रा में नियमित रूप से आइसक्रीम खाते हैं तो इससे डायबिटीज, मोटापा और खडजेसन की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही, यह आदत आपकी नींद को प्रभावित कर अनिद्रा का कारण बन सकती है।



कुछ लोग दिनभर की थकान के बाद रात के खाने के साथ या उसके बाद ठंडी-मीठी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे मूड फ्रेश करने वाला डेजेंट मानते हैं, तो कुछ इसे खाने के बाद होने वाली क्रेविंग का आसान समाधान समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिनर के बाद आइसक्रीम खाना शरीर के लिए सुरक्षित है या इससे पाचन, वजन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है?

निशाना

यार से शिकवा..!



दिनेश मालवीय 'अश्क'

यार से शिकवा तो मैं अब भी नहीं करता हूं मगर मिलने को उससे जी नहीं करता। जो किताबों में पढ़ा जीने लगा उसको जानता गर सच तो यह गलती नहीं करता। शख्स वह काफी मुझे अनमोल लगता है वह बड़ाई कुछ कभी खुद की नहीं करता। है जिसे सच्ची समझ अपने धरम की वह दूसरे धरमों की बेअदबी नहीं करता। इस शहर ने उसको रसवा किस क्रुदर किया पर बुराई 'अश्क' तो उसकी नहीं करता।

नॉलेज

दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है आर्कटिक के नीचे छिपा कार्बन का भंडार

रिसर्च में सामने आया है कि आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपा कार्बन दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साल 2050 तक यह इलाका कार्बन सोखने के बजाय उसे बाहर छोड़ना शुरू कर देगा। पुराने मॉडल्स में गहरी बर्फ के नीचे छिपे इस खतरे को नजरअंदाज किया गया था। अब नई स्टडी ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।

आर्कटिक की बर्फ दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। साइंस एडवांस नाम के जर्नल में छपी एक नई रिसर्च ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। धरती का उत्तरी हिस्सा अब तक एक बड़े स्पंज की तरह काम करता था। यह हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता था। लेकिन नई स्टडी में एक बहुत ही डराने वाली बात सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 के दशक तक आर्कटिक कार्बन सोखना बंद कर देगा। इसके बाद यह खुद कार्बन छोड़ना शुरू कर देगा। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी। पुराने क्लाइमेट मॉडल्स में सतह के नीचे छिपे कार्बन को नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अब गहराई में छिपे इस

पुराने कार्बन को भी कैलकुलेट किया गया है। यह धरती के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है।

सालों से क्लाइमेट मॉडल्स यह मानकर चल रहे थे कि उत्तरी इलाके हमारे लिए ढाल बनेंगे। वैज्ञानिकों को लगता था कि यह इलाका इस सदी के अंत तक कार्बन सोखता

रहेगा। बढ़ते तापमान से बर्फ पिघल सकती है और ग्रीनहाउस गैसें निकल सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही वहां पौधों की ग्रोथ भी तेज होती है। इससे वातावरण से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जा सकती है। इसी वजह से पुराने मॉडल्स बताते थे कि यह इलाका कार्बन का नेट एब्जॉर्बर बना रहेगा। लेकिन नई रिसर्च कहती है कि यह तस्वीर पूरी तरह से अधूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पुराने मॉडल्स में एक बड़ी गलती थी। उन्होंने गहराई में छिपे पुराने कार्बन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। यह कार्बन मुख्य रूप से साइबेरिया और अलास्का में बर्फ के नीचे दबा है। अगर यह बाहर आ गया तो क्लाइमेट चेंज को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा।



के मुकाबले थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में अतिरिक्त शुगर और फैट शरीर में जमा होने लगते हैं। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और कुछ समय बाद अचानक गिर भी सकता है, जिसके कारण देर रात भूख या सुस्ती महसूस हो सकती है।

वहीं एनसीबीआई की रिसर्च यह भी बताती है कि लोगों को डिनर के बाद दूध से बनी आइसक्रीम खाने से पीट भारी लगना, गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। खासकर जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके लिए यह परेशानी और बढ़ सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, भोजन के तुरंत बाद बहुत ठंडी चीजें खाने से कुछ लोगों का पाचन प्रभावित हो सकता है। हालांकि इसका असर हर व्यक्ति में अलग होता है। जोखिम डायबिटीज सेंटर के अनुसार फैट और शुगर पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। आइसक्रीम में भी फैट और शुगर मौजूद होते हैं। जब आप ऑयली भोजन करते हैं और इसके बाद आइसक्रीम खाते हैं तो इससे पेट में

गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट दर्द और सुस्ती की समस्या महसूस हो सकती है। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित 2024 के एक स्टडी में टाइप 2 डायबिटीज के कुछ रोगियों को बिना चीनी वाली आइसक्रीम और कुछ को चीनी वाली आइसक्रीम दी गई। इस अध्ययन में पाया कि जिन लोगों को चीनी वाली सामान्य आइसक्रीम दी गई थी, उनकी ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल अन्य की तुलना में अधिक था। इससे पता चलता है कि डायबिटीज के रोगियों को रात के समय आइसक्रीम खाने से बचना चाहिए।

एनसीबीआई की रिसर्च बताती है कि हाई-फैट और हाई-शुगर फूड्स रात में खाने से स्लीप क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा, दूध व दूध से बनी चीजों के सेवन से भी नींद के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। दरअसल, रात में ठंडी चीजें खाने से अलर्टनेस बढ़ जाती है। साथ ही, पेट से जुड़ी परेशानियों की वजह से भी नींद में खलल पड़ सकता है।

अजब-गजब

भारत में भी है एक कोरिया, प्राचीन इतिहास के कारण पड़ा छत्तीसगढ़ के इस जिले का नाम

आपने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बारे में तो खूब सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक कोरिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक जिले का नाम उसके इतिहास की वजह से कोरिया रखा गया है।

कोरिया शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग और उसके परमाणु कार्यक्रम की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक कोरिया है? और वहां ना तो कोई तानाशाह है, ना परमाणु बम और ना ही कोई सैन्य राजनीति। यह कोरिया छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक सुंदर जिला है।

कोरिया जिला छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं सरगुजा, सूरजपुर और अनुपपुर जिले से लगती है। जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर है। यह क्षेत्र अपनी घने जंगलों, खनिज संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। लेकिन

सबसे दिलचस्प बात इसका नाम है। लोग जब भी इस जिले का नाम सुनते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। आज हम आपको इसके नाम की हिस्ट्री बताते हैं।

प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कोरिया पठार कहा जाता था। यहां कोल वंश के राजा और बलेंद शासक राज्य करते थे। उनकी राजधानी कोरियागढ़ थी। इन्होंने राजाओं और स्थान के नाम पर पूरे इलाके को कोरिया कहा जाने लगा। 1600 ईस्वी से पहले का इतिहास थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन ब्रिटिश काल में यह

कोरिया रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वतंत्र भारत में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यह कोरिया जिला बना दिया गया। आज यह जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां के लोग मुख्य रूप से किसानों और जंगल से जुड़े काम करते हैं। कोरिया जिले में कोयला, हीरा और अन्य खनिजों की प्रचुरता है।



न्यूज विंडो

बिहार एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी को सर्व समाज ने दी श्रद्धांजलि



गंजबासौदा। स्थानीय महाराणा प्रताप बस स्टैंड स्थित श्री महाराणा प्रताप चौक पर बिहार एनकाउंटर में मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की आत्मशान्ति के लिए सर्व समाज द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने दिवंगत तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घटना को लेकर प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि भरत भूषण तिवारी बिहार के बिलौटी गांव के निवासी थे और लंबे समय से बाढ़ पीड़ितों एवं दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उनका कहना था कि तिवारी लगातार सरकार और प्रशासन के समक्ष पीड़ितों की समस्याएं उठाते रहे, लेकिन इसी संघर्ष के कारण उन्हें कथित फर्जी एनकाउंटर का शिकार होना पड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संतोष शर्मा ने कहा कि भरत तिवारी समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज थे। वे दलितों और बाढ़ प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने साजिश के तहत उनकी हत्या करवाई है। उन्होंने मांग की कि इस कथित फर्जी एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिससकर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सोलंकी ने भी भरत तिवारी के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं विकास शर्मा ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

अग्निवीर लोकेंद्र के घर लौटने पर जोरदार अभिनंदन

गंजबासौदा। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत चयनित युवा लोकेंद्र कुशवाह के ट्रेनिंग पूर्ण कर पहली बार घर लौटने पर नगर में उदसाह और गौरव का माहौल देखने को मिला। रेलवे स्टेशन से लेकर उनके निवास वार्ड क्रमांक 08 अयोध्या बस्ती तक परिजनों, मित्रों और क्षेत्रवासियों ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार अयोध्या बस्ती निवासी लोकेंद्र कुशवाह, पिता राधेश्याम कुशवाह, का अगस्त 2025 में अग्निवीर योजना के तहत चयन हुआ था। चयन के बाद वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए गए थे। प्रशिक्षण पूर्ण कर मंगलवार को पहली बार गंजबासौदा लौटने पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में परिजन एवं वार्डवासी रेलवे स्टेशन पहुंचे। जैसे ही लोकेंद्र स्टेशन पहुंचे, उनका फूल-मालाओं से अभिनंदन किया गया। ढोल-नगाड़ों की गूंज और भारत माता के जयकारों के बीच उनका स्वागत जुलूस निकाला गया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने पुष्पपर्चा कर उनका सम्मान किया। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। परिजनों ने कहा कि लोकेंद्र की उपलब्धि पूरे परिवार ही नहीं, बल्कि नगर और क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत है। वार्डवासियों ने भी उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को देश सेवा के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा लोकेंद्र से मिलेगी।

ट्रेन में सीट के लिए प्लेटफार्म छोड़ पटरी पर खड़े हो रहे यात्री



गंजबासौदा। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बीना की ओर से आने वाली मेमो ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। योजना बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफार्म पर इंतजार करने के बजाय नीचे उतरकर सीधे पटरी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि ट्रेन आते ही जल्दी से उसमें सवार हो सकें। यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्टेशन पर सुबह और शाम के समय मेमो ट्रेन के कारण के दौरान यह स्थिति अधिक देखने को मिलती है। यात्री प्लेटफार्म से नीचे उतरकर ट्रैक के किनारे खड़े हो जाते हैं और ट्रेन रुकने से पहले ही दरवाजे के सामने पहुंचने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि रेलवे सुरक्षा नियमों की भी खुलेआम अनादेखी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी इसी तरह पटरी के पास खड़े नजर आते हैं। ट्रेन के अचानक आने, फिसलन या भीड़ के धक्के से किसी भी समय गंभीर दुर्घटना हो सकती है। बावजूद इसके यात्री जल्दबाजी और सुविधा के कारण यह खतरनाक तरीका अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रेलवे नियमों के अनुसार प्लेटफार्म छोड़कर पटरी पर उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन स्टेशन पर इस पर प्रभावी रोक नहीं दिखाई दे रही। लोगों का कहना है कि स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, अनाउंसमेंट के जरिए लगातार चेतावनी दी जाए और ऐसे यात्रियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले इस लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके।

जमीन पर दबंगों का कब्जा, रेलवे और यातायात विभाग मौन

अनूपपुर। अनूपपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए बनाई गई जगह पर इन दिनों नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और दबंगों के वाहनों का कब्जा देखा जा रहा है। इससे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखे गए मार्ग पर दिनभर चारपहिया वाहन खड़े रहते हैं, जिससे लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है। रेलवे स्टेशन पर पैदल मार्ग और प्रवेश-निकास मार्ग को अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग से मुक्त रखना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। विभिन्न शहरों में रेलवे परिसरों के बाहर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर रेलवे एवं यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है

शहडोल जिले की कोतवाली पुलिस ने खुद को गौरक्षक बताकर की मारपीट

लोगों को बंधक बनाकर अवैध वसूली और लूटपाट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

शहडोल। दोपहर मेट्रो

जिले की कोतवाली पुलिस ने खुद को गौरक्षक बताकर लोगों से मारपीट, लूटपाट और अवैध वसूली करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाण्डवनगर निवासी नरेश प्रसाद पनिका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह अपने तीन पालतू बैलों को खेती कार्य के लिए अनूपपुर भेज रहे थे, तभी तीन लोग कार से पहुंचे और खुद को गौरक्षक बताकर पशु चोरी का आरोप लगाने लगे।

शहडोल जिले की कोतवाली पुलिस ने खुद को गौरक्षक बताकर लोगों से मारपीट, लूटपाट और अवैध वसूली करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पशु व्यापारियों और ग्रामीणों को निशाना बनाकर उनसे जबरन पैसे वसूलने का प्रयास करते थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस के अनुसार पाण्डवनगर निवासी 64 वर्षीय नरेश प्रसाद पनिका ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वे अपने तीन पालतू बैलों को खेती के कार्य



के लिए अनूपपुर जिले के ग्राम सिलवारी भेजने के लिए पिकअप वाहन में लोड कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 10 बजे कार से पहुंचे तीन लोगों ने खुद को गौरक्षक बताते हुए उन पर पशुओं की चोरी कर कटाई के लिए ले जाने का आरोप लगाया।

शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने फरियादी और उसके साथ मौजूद श्रमिकों के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद डंडों, लोहे की रॉड और थप्पड़ों से मारपीट की गई। आरोपियों ने धमकाते हुए 50 हजार रुपये की मांग भी की।

विरोध करने पर फार्म हाउस ले जाकर बनाया बंधक, मोबाइल और नकदी छीने

विरोध करने पर आरोपी फरियादी और उसके साथियों को जबरन वाहन में बैठाकर अडना नदी के किनारे स्थित एक फार्म हाउस ले गए। वहां उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन और नगदी भी छीन ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी विवेचना के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अनूज सिंह, आशुतोष चतुर्वेदी और राजेश बेगा शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों का किसी संगठित गिरोह से संबंध तो नहीं है।

जमीन विवाद को लेकर चले लाठी-डंडे



छिंदवाड़ा। दोपहर मेट्रो

जिले के जुवारादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत नवगांव पुलिस चौकी के बोरेदेही खुर्द गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चार दिन पहले दो पक्षों के बीच हुए विवाद में लाठी-डंडों और पत्थरों से जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक घायल को मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

विद्युत वितरण कंपनी की नई व्यवस्था बनी परेशानी का कारण

जबलपुर। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का शबब बन रही है। अप्रैल 2026 से शुरू हुई योजना के तहत जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले किसानों के खेतों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और अब बिजली का बिल खपत के आधार पर वसूला जा रहा है। बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर व्यवस्था के विरोध में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अब इनका कहना है कि यदि सरकार और बिजली विभाग ने व्यवस्था में बदलाव नहीं किया तो वे संगठित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

कान्हा के मुक्की क्वॉरेंटाइन सेंटर में उपचार के दौरान एक और बाघ की मौत



मंडला। दोपहर मेट्रो

कान्हा टाइगर रिजर्व में के नाइन डिस्टेम्पर वायरस का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। इसी क्रम में कान्हा के मुक्की क्वॉरेंटाइन सेंटर में उपचार के दौरान एक और बाघ की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले दो महीनों

में इस वायरस से मरने वाले बाघों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। प्रारंभिक जांच में बाघ में के नाइन डिस्टेम्पर वायरस के लक्षण पाए गए थे। इसके बाद विशेषज्ञों की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया।

अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

कृषि मंडी में शुल्क बढ़ोत्तरी का किया विरोध

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

कृषि उपज मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन भेजकर मंडी शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार करने तथा अशा शुल्क वापस लेने की मांग की है।

ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश के व्यापारी एक किसान पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालात के कारण डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री और दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं किसानों की उपज के दाम अपेक्षाकृत कम होने से किसान और व्यापारी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में मंडी शुल्क में वृद्धि करना न तो किसानों के हित में है और न ही व्यापारियों के। व्यापारी संघ ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि मंडियों को व्यवस्थित रूप से बहाल कर किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश की मंडियों पर मंडी बोर्ड द्वारा मनमानी की जा रही है,



जिससे मंडियों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीण सड़कों और गौशालाओं के नाम पर मंडी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव व्यापार व्यवस्था को और कठिन बना देगा। इससे व्यापार मंडियों से बाहर स्थानांतरित होने लगेंगे और अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलने की आशंका भी बढ़ेगी। संघ का उल्लेख किया कि मंडियों को व्यवस्थित रूप से बहाल कर किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश की मंडियों पर मंडी बोर्ड द्वारा मनमानी की जा रही है,

किसान एवं व्यापारी हित में निर्णय लेते हुए मंडी शुल्क वृद्धि के आदेश को वापस लेना चाहिए और मंडी बोर्ड की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। व्यापारी संघ ने यह भी कहा कि प्रत्येक मंडी अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं के अनुसार बेहतर ढंग से संचालित हो सकती है। यदि शासन व्यापारी प्रतिनिधिमंडल को समय प्रदान करे तो वे मंडियों की विभिन्न समस्याओं और उनके व्यावहारिक समाधान शासन के समक्ष विस्तार से रख सकते हैं।

मेट्रो एंकर

मंडीटीप में साइबर जागरूकता पखवाड़े ने जगाई डिजिटल सुरक्षा की मिसाल

सात दिवसीय पखवाड़ा बना ठगी से बचाव का प्रमुख मूलमंत्र

मंडीटीप। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश एवं देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों के दौर में लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता पखवाड़े का आयोजन 23 से 30 जून तक चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, एसडीओपी शीला सुराणा के निर्देश पर सतलापुर थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र के मैक्सन कंपनी में साइबर जागरूकता पखवाड़ा का आगाज किया गया जहां उप निरीक्षक अरुणा साना ने कंपनी में श्रमिकों को जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक किया उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी, अश्लील वीडियो पैसों का ट्रांजैक्शन, बैंकों के नाम पर धोखाधड़ी सहित अनेक हथकंडे अपनाए जाते हैं जिन पर हमें जागरूक रहना अति आवश्यक है। पुलिस प्रशासन का यह जागरूकता अभियान जनजागरण अभियान बनकर उभर रहा है। पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों



पर आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों को साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया जाएगा।

अभियान के दौरान बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया लिंक, नकली वेबसाइट और ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के

जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। कार्यक्रमों में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उपस्थित लोगों को ऑनलाइन लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, मजबूत पासवर्ड के उपयोग, दो-स्तरीय सुरक्षा तथा सदिग्ध लिंक से बचने के

बारिश से पहले भी नहीं चेता जिला अस्पताल, जलभराव का खतरा

शहडोल। दोपहर मेट्रो

संभागीय मुख्यालय स्थित 300 बिस्तरों वाले जिला चिकित्सालय में मानसून की आहट के बावजूद जल निकासी व्यवस्था की समुचित तैयारी नहीं की गई है। अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर नालियां कच्ची पड़ी हुई हैं, जबकि कई जगह नालियों में गाद और कचरा जमा होने से पानी के निकास में बाधा बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बारिश के दौरान जिला अस्पताल परिसर में जलभराव की गंभीर स्थिति निर्मित हो गई थी। अस्पताल के वाडों, गलियारों एवं आवागमन मार्गों तक पानी पहुंच गया था, जिससे मरीजों, उनके परिजनों तथा अस्पताल स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद इस वर्ष भी व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई, पक्की जल निकासी व्यवस्था एवं ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया तो आगामी बारिश में फिर से अस्पताल परिसर जलमग्न हो सकता है। इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। सवाल यह उठता है कि आखिर जिला अस्पताल प्रबंधन किस बड़ी घटना या दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। नागरिकों ने कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक सुधारवाचक कार्रवाई कराने की मांग की है।

मंडीटीप में साइबर जागरूकता पखवाड़े ने जगाई डिजिटल सुरक्षा की मिसाल

बारों में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, बैंकिंग जानकारी या व्यक्तिगत गोपनीय सूचनाएं साझा न करें। साथ ही साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक 1930 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। साइबर जागरूकता पखवाड़े के माध्यम से यह संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया कि डिजिटल युग में सुरक्षित रहना केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है। अभियान ने लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति नई चेतना जगाई है और डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। जागरूकता ही सुरक्षा है, सतर्कता ही बचाव है यदि हमें साइबर अपराधों से बचना है है तो पुलिस प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना हारा अन्यथा हम भी इसी श्रेणी में साइबर ठगी महसूस कर सकेंगे इसी संदेश के साथ पखवाड़े का सफल संचालन किया जा रहा है।

गुस्साएं परिजनों एवं अहिरवार समाज के लोगों ने दमोह जबलपुर मार्ग को किया जाम, पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

हाथटेला का किराया मांगने पर फल विक्रेता ने युवक को मारा चाकू, मौत

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

नगर में रात्रि 8.20 बजे एक नवयुवक को सीने में चाकू मार दिया जिससे उसकी कुछ ही देर अस्साल पहुंचते ही मौत हो गई। गुस्साएं परिजनों ने मुख्य सड़क दमोह जबलपुर मार्ग पर 9 बजे से जाम लगा दिया समाचार लिख दिए जाने तक जाम लगा हुआ था। इसके अलावा लोगों ने बाहर से आए फल विक्रेताओं के फल एवं हाथ टेला सड़क पर पलटा दिए। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सैकड़ों की संख्या में अहिरवार समाज के महिला पुरुष अस्पताल एवं मुख्य सड़क मार्ग पर आकर बैठ गए।

अतुल पिता वीरनलाल अहिरवार 25 निवासी वार्ड क्रमांक 5 जिसने हाट बाजार में



अपना हाथटेला किराए पर फल बेचने के लिए दमोह के फल विक्रेता को दिया था। रात्रि में जब अतुल हाथटेला का किराया लेने मुख्य सड़क मार्ग पर पहुंचा तो फल विक्रेता से

किराए को लेकर बहस होने लगी। फल विक्रेता ने 50 रूपए किराया फेंककर दिया और हाथ लिए चाकू को अतुल के सीने में मार दी। चाकू सीने के बाएं साइड लगी जिससे

अतुल का खून गिरने लगा और जमीन पर गिर पड़ा फल विक्रेता अपनी फल की दुकान को छोड़कर भाग गया। स्थानीय लोग अतुल को नगर की अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टर ने

अतुल को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने मौके पर आकर कई फल विक्रेताओं को पूछताछ के लिए पुलिस थाना ले गई। हमला करने वाला व्यक्ति की जानकारी पुलिस जुटा रही है। बताया जा रहा है कि दो लोग फल बेच रहे थे उन्हीं से अतुल का वाद विवाद हुआ था। हमलवार दमोह के बताए जा रहे हैं। अस्पताल में परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है बताया गया कि अतुल की दो माह पहले ही शादी हुई थी। मौके पर एसडीएम सीजी गोस्वामी, एसडीओ पी अर्चना अहिर, नगर निरीक्षक रावेन्द्र बागरी के अलावा पुलिस थाना बल का मौके पर मौजूद हैं साथ ही पांच थानों का बल बुलाया गया है। समाचार खिले जाने तक जाम लगा हुआ था।



न्यूज विंडो

आपरेटर की अमर्यादित भाषा के विरोध में वार्डवासियों ने दिया आवेदन

तेंदूखेड़ा। नगर में जल सप्लाई को लेकर वैसे ही नगर वासी परेशान हैं चाहे नर्मदा जल हो या नगर परिषद के बोर से जल सप्लाई हो सब जमीनी स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते ठीक तरह से नहीं चल पा रही हैं। वार्ड 8 में जल सप्लाई करने वाला आपरेटर लोगों से अभद्र भाषा में बात करता है। वहीं दूसरी ओर नर्मदा जल का समय निश्चित नहीं है। आखिरकार वार्ड क्रमांक 8 के लोगों ने नगर परिषद के जल सप्लाई करने वाले आपरेटर से परेशान होकर हटाने की मांग को लेकर जनसुनवाई में एसडीएम को आवेदन दिया है। लोगों ने बताया कि गौशाला वाले रास्ते में पिछले 6 दिनों से जल सप्लाई नहीं हुई है। हम लोगों के यहां नर्मदा जल का पानी बहुत ही देर में आता है जैसे ही पानी आता है उसी समय 1 घंटा पूरा होने पर सप्लाई बंद हो जाती है। इसलिए नगर परिषद के बोर से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन आपरेटर हम लोगों से ठीक तरह से बात नहीं करता है बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। एसडीएम से लोगों ने मांग की है कि दूसरे आपरेटर को हमारे वार्ड में नियुक्त किया जाए। इस दौरान सजीत नामदेव, प्रशांत जैन, अंकित नेमा, कमलेश, शोभा सोनी, चोखेलाल नामदेव, पुखराज बिंदुआ, सौरभ श्रीवास्तव, बालचंद्र जैन, दीपक जैन, सुनील जैन, संदीप सिंह ठाकुर आदि उपस्थित रहे। एसडीएम सीजी गोस्वामी ने कहा कि वार्ड 8 के लोगों ने आपरेटर के खिलाफ आवेदन दिया है सीएमओ को आपरेटर के उपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

सफाई व्यवस्था पर सवाल, मानसून से पहले वार्डों में गंदगी का अंबार

तेंदूखेड़ा। मानसून की दस्तक से पहले नगर परिषद की सफाई व्यवस्था सवाल के घेरे में है। नगर के विभिन्न वार्डों में फैली गंदगी, कचरे के ढेर और चोक पड़ी नालियां आने वाले दिनों में गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती हैं। जबकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों की आशंका को देखते हुए शासन एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार साफ-सफाई बनाए रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील कर रहे हैं। करीब 20 हजार आबादी वाले तेंदूखेड़ा नगर के 15 वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं तथा नालियां महीनों से साफ नहीं होने के कारण मलबे और गंदगी से भरी पड़ी हैं।



अफवाहों के चलते इमामबाड़ा क्षेत्र में एकत्रित मुस्लिम समाज, पुलिस तैनात

धार। शहर में सोशल मीडिया पर फैले भ्रामक संदेशों और एक अदालती फैसले को लेकर उड़ी अफवाह के कारण बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इमामबाड़ा के बाहर एकत्रित हो गए। हालांकि पहले से ही पुलिसबल मौके पर तैनात था, इसके कारण कोई बड़ा विवाद तो नहीं हुआ। किंतु करीब ढाई घंटे तक मुस्लिम समाज के लोग क्षेत्र में मौजूद रहे। इस दौरान समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाली थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नाँगाव, कोतवाली और अन्य थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। डीआरपी लाइन से जवानों की तैनाती की गई, वहीं ब्लैक कमांडो को भी मौके पर भेजा गया। हालांकि, पुलिस की मुस्तीडी और समझाव के बाद भीड़ को शांत कर घंटों की ओर रवाना कर दिया गया है। इसी मांग और विरोध के चलते मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तत्काल वहां पहुंचा। एसपी विजय डावर ने बताया कि पुलिस ने काफी देर तक युवाओं को समझाया और न्यायालय की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद सभी युवा मान गए और अपने-अपने घरों की ओर लौट गए। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में और शांतपूर्ण है। पुलिस प्रशासन ने किसी भी अग्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियात के तौर पर शहर के पीडब्ल्यूडी भवन, हटवाड़ा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पॉइंट लगा दिए हैं। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और शहर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।

मेट्रो एंकर

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के प्रकरणों की समीक्षा की

जर्जर शाला भवनों में कक्षाएं संचालित न किए जाने के निर्देश

बालाघाट। दोपहर मेट्रो

बालाघाट कलेक्टर मृगाल मोणा ने विभिन्न विभागों के प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक और सहयोग्य आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को संख्त निर्देश दिए कि जिले के किसी भी जर्जर शाला भवन में कक्षाएं संचालित न की जाएं।

कलेक्टर ने चेतावनी दी कि वर्षा ऋतु में यदि किसी विद्यालय की छत से पानी टपकने या दीवारों का प्लास्टर गिरने जैसी शिकायत मिली, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट में सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में 249 भवन जर्जर स्थिति में हैं।



कोतवाली क्षेत्र में 20 दिनों में 6 चोरी की वारदातें, ताले चटका रहे बेखौफ बदमाश

शहर के विनायक कुंज में दिन दहाड़े चोरी नगदी और आभूषण चुरा ले गए बदमाश

धार। दोपहर मेट्रो

शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत इन दिनों बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें अब रात के अंधेरे की भी जरूरत नहीं रही, वे दिन के उजाले में पुलिस की गश्ती को टेंगा दिखाते हुए बेधड़क वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 20 दिनों के भीतर कोतवाली क्षेत्र में एक के बाद एक 6 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक पूरी तरह खाली हैं। त्रिमूर्ति नगर, तुलसी नगर, विनायक कुंज और भोज नगर जैसे पॉश और व्यस्त इलाकों में लगातार हो रही वारदातें पुलिस की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करती हैं।

पुलिस की कार्यशैली पर दोहरा रवैया तब साफ उजागर होता है जब हम बदनाम को घटना को देखते हैं। बीते 3 जून को बदनाम में भाजपा के एक कद्दावर नेता के घर हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा करने के लिए एसपी सचिन शर्मा ने तत्काल एसआईटी का गठन कर दिया था। पुलिस टीमों ने आनन-फानन में राजस्थान तक दबिश दी, आरोपियों को दबोचा और जमकर वाह-वाही बटोरी। क्या पुलिस की मुस्तीडी सिर्फ वीआईपी चेहरों के लिए है? कोतवाली क्षेत्र के आम नागरिकों की मेहनत को कमाई पर जो डाका डल रहा है, क्या उसका सुराग लगाने के लिए कोई एसआईटी बनेगी या इन फाइलों को भी हमेशा की तरह धूल खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा? पुरानी फाइलें भी धूल खा रही हैं



यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पूर्व भी मोहन टॉकीज के पास स्थित परिसर में बने भद्रकाली मंदिर से माताजी के आभूषण चोरी हुए थे, जिसका आज तक कोई अता-पता नहीं है। इसी तरह मोहन टॉकीज की मैकेनिक वाली गली से कई वजनदार मोटर्स चोरी हुईं, जिन्हें ट्रेस करने में पुलिस नाकाम रही। विनायक कुंज में दिनदहाड़े हुई वारदात ने धार वासियों को दहशत में डाल दिया है। जब लोग अपने घरों में दिन में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो रात्रि गश्ती

का दावा कितना खोखला है, यह समझा जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या धार पुलिस आम जनता के इस दर्द को समझेगी या फिर इन वारदातों को भी ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस टीमों आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी है, चोरियों की वारदातों में इंदौर की गैंग के कुछ सदस्य ट्रेस हुए हैं, जल्द ही शहर में हुई चोरियों की वारदातों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

पिछले दिनों हुई चोरी की वारदातें

16 जून को त्रिमूर्ति नगर में तरुण खत्री के घर में मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर तिजोरी से सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली और नकदी सहित डेढ़ लाख की चोरी।

13 जून को शहर के समीप ग्राम हिममतगढ़ में मानसिंह के घर के बाहर स अज्ञात बदमाश फरियादी की 6 बड़ी बैंस और 4 पाउंड ले गए। कुल कीमत करीब पांच लाख रुपए आंकी गई थी।

15 जून की शाम भोज नगर में सुनीता पति प्रवीण राण के सून मकान का ताला चटकाकर अलमारी में रखी एक जोड़ी चांदी की पायजेब और सोने के टॉप्स चोरी की कुल कीमत 60 हजार से अधिक थी।

6 से 07 जून की रात्रि आदर्श रोड त्रिमूर्ति नगर में अयान मोहम्मद की दुकान के दरवाजे का नकुचा तोड़कर लाइट स्विच, पिन्डियन ड्राई, आर्मीचर, रुटर, स्टार्टर मोटर और भंगार सामान चुराकर बदमाश फरार हो गए थे।

2 से 3 जून के बीच तुलसी नगर में कपिल यादव के मुख्य दरवाजे और छत की टावर का दरवाजा उधकाकर अलमारी से पायजेब और 25 हजार नाद लेकर बदमाश फरार हुए थे।

22 जून सोमवार को दिनदहाड़े विनायक कुंज मांडू रोड मुकेश कुमार पत्नी शिक्षिका होने से स्कूल गई थीं और मुकेश काम पर थे। बदमाशों ने दिनदहाड़े मकान साफ कर दिया और हजारों के आभूषण, नकदी के साथ दीवार पर टंगी एलईडी भी उखाड़ ले गए।

जनसुनवाई में पहुंचे 25 के करीब आवेदन कई विभागों के अधिकारी रहे अनुपस्थित



तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

जनसुनवाई में क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं से संबंधित लगभग 20 से 25 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सी.जी. गोस्वामी, जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागरी, तहसीलदार विवेक व्यास, बीईओ नितेश पांडे नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी, महिला एवं बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर राजू नामदेव तथा अन्य अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। कुछ विभागों के अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेजा। विद्युत विभाग से

सुधीर पटेरिया सहित नगर परिषद एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि लोक निर्माण विभाग की एसडीओ मनीषा मोगनिया एवं जल ससाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सी.जी. गोस्वामी, जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागरी, तहसीलदार विवेक व्यास, बीईओ नितेश पांडे नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी, महिला एवं बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर राजू नामदेव तथा अन्य अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। कुछ विभागों के अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेजा। विद्युत विभाग से

सुधीर पटेरिया सहित नगर परिषद एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि लोक निर्माण विभाग की एसडीओ मनीषा मोगनिया एवं जल ससाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सी.जी. गोस्वामी, जनपद पंचायत सीईओ मनीष बागरी, तहसीलदार विवेक व्यास, बीईओ नितेश पांडे नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी, महिला एवं बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर राजू नामदेव तथा अन्य अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। कुछ विभागों के अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेजा। विद्युत विभाग से

तेंदूखेड़ा में कांग्रेस का विशाल धरना-प्रदर्शन, महंगाई, किसानों एवं युवाओं के मुद्दों पर सौंपा 17 सूत्रीय ज्ञापन

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मंगलवार को स्थानीय बस स्टैंड परिसर में दोपहर 2 बजे से विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्याओं, युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।

धरना-सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण आम जनता, किसान और युवा वर्ग लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है, जिससे परिवहन लागत बढ़ी है और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दामों में भी लगातार वृद्धि हुई है। जबरा विधानसभा प्रभारी रमाकांत यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानक पटेल, पंडित मनु मिश्रा, दृगपाल सिंह, जबरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष



ओम प्रकाश शर्मा, नोहटा संतोष रजक, तेजगढ़ मोहन आदिवासी, तेंदूखेड़ा नीलेश यादव, गोविंद तिवारी, रघुनाथ यादव, सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश और देश की भाजपा सरकार युवाओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को खाद, बीज एवं अन्य कृषि संसाधन उपलब्ध कराने में भी विफल रही है। किसानों को पहले आसानी से खाद उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था के कारण उन्हें कई दिनों तक

कम्प्यूटर सेंटर, पटवारी एवं तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों को डीएपी खाद की कमी, महंगे डीजल और कृषि कार्यों में बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर, व्यापारी और आम नागरिक सभी प्रभावित हैं। धरना-सभा के पश्चात बस स्टैंड से तारादेही तिराहा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशाल जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन (म.प्र.)	
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन में कार्यालयीन एवं अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में मूद्रण कार्य करने के संबंध में वर्ष 2026-27 के लिए ई-निविदा आमंत्रण।	
प्रथम निविदा	
1	निविदा विवरण
2	निविदा दस्तावेज अनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता
3	ऑनलाइन निविदा जारी करने की तिथि एवं समय।
4	ऑनलाइन निविदा क्रय करने की तिथि एवं समय।
5	ऑनलाइन निविदा क्रय प्री-बिड मीटिंग।
6	ऑनलाइन निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय।
7	ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय।
8	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोले जाने की तिथि एवं समय।
9	वित्तीय निविदा ऑनलाइन खोले जाने की तिथि एवं समय।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- रायसेन	
जी-14783/26	

महज 27 साल की उम्र में रच रहे कीर्तिमान

16 विश्वकप में 16 गोल एमबाप्पे का रिकॉर्ड देखकर फुटबॉल जगत हैरान



न्यूयॉर्क। फिफा डेवलपमेंट में इराक के खिलाफ मुकाबला किलियन एमबाप्पे के करियर का 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच था। इस खास अवसर को उन्होंने दो गोल दागकर और भी यादगार बना दिया। 14वें मिनट में माइकल ओलीसे के पास पर एमबाप्पे ने शानदार लेफ्ट फुट शॉट लगाकर फ्रांस को बढ़त दिलाई। इसके बाद 54वें मिनट में उन्होंने दूसरा गोल कर टीम की जीत लगभग तय कर दी। फ्रांस ने मुकाबला 3-0 से जीता और राउंड ऑफ-32 में जगह बना ली। विश्वकप इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर इराक के खिलाफ दूसरा गोल एमबाप्पे के विश्वकप करियर का 16वां गोल था। इसके साथ उन्होंने जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी कर ली। सबसे खास बात यह है कि एमबाप्पे ने यह उपलब्धि सिर्फ 16 विश्वकप मैचों में हासिल की है, जबकि क्लोज ने 24 मुकाबले खेले थे। इराक के खिलाफ दो गोल करने के साथ एमबाप्पे ने विश्वकप इतिहास का एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब उनके नाम विश्वकप में छह ऐसे मैच हैं, जिनमें उन्होंने दो या उससे ज्यादा गोल किए हैं। यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा विश्वकप इतिहास में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा बताता है कि बड़े मंच पर एमबाप्पे सिर्फ गोल नहीं करते, बल्कि मैच का रुख बदलने की क्षमता भी रखते हैं। एमबाप्पे ने 25 मार्च 2017 को लक्जमबर्ग के खिलाफ फ्रांस के लिए डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी। विश्व फुटबॉल ने उन्हें वास्तव में

उज्बेकिस्तान की टीम का सफर गुप चरण में ही थमा

पुर्तगाल ने नॉकआउट की ओर बढ़ाए कदम, गुप में शीर्ष पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दमदार प्रदर्शन

हुआस्टन, एजेंसी

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो गोल की मदद से पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। पुर्तगाल ने पिछले मैच में ड्रॉ खेला था, लेकिन टीम इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही। टीम के लिए रोनाल्डो ने दमदार प्रदर्शन किया। रोनाल्डो ने मैच के बाद आई एम बैक, यानी मैं वापस आ गया हूँ कहा। रोनाल्डो पिछले मैच में गोल नहीं कर सके थे, लेकिन इस मैच में दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान की टीम का सफर गुप चरण में ही थम गया। पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो के अलावा नूनो मेंडेस और राफेल लियाओ ने एक-एक गोल किए। वहीं, उज्बेकिस्तान के नेमातोव ने आत्मघाती गोल किया।

अंक तालिका का हाल

इसके साथ ही पुर्तगाल गुप के चार अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है और उसने नॉकआउट के लिए दावा मजबूत कर लिया है। पुर्तगाल के दो मैचों में एक जीत और एक ड्रा से चार अंक हो गए हैं। दूसरे स्थान पर कोलंबिया है जो एक मैच में एक जीत के साथ तीन अंक लेकर दूसरे नंबर पर है। कोंगो डीआर एक अंक के साथ तीसरे और उज्बेकिस्तान दो मैच में दो हार के साथ चौथे स्थान पर है।



रोनाल्डो ने शुरुआत से ही अपनाया आक्रामक रुख

इस मैच में शुरुआत से ही रोनाल्डो ने आक्रामक रुख अपनाया। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मिनट में ही गोल दागा। रोनाल्डो डीआर कागो के खिलाफ टीम के पिछले मैच में गोल नहीं कर सके थे और इस मैच में उन पर दबाव था। हालांकि, रोनाल्डो ने दबाव को हावी नहीं होने दिया और छठे मिनट में ही गोल दाग कर टीम को बढ़त दिला दी। रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पहले ही हाफ में अपना दूसरा गोल दागा। रोनाल्डो ने 39वें मिनट में शानदार गोल किया और उज्बेकिस्तान के खिलाफ टीम को 3-0 से आगे किया। पुर्तगाल के लिए दूसरा गोल नूनो मेंडेस ने 17वें मिनट में किया। रोनाल्डो पहला हाफ समाप्त होने के कुछ सेकंड पहले अपना तीसरा गोल करने के करीब थे, लेकिन इससे चूक गए।

पुर्तगाल के लिए विश्व कप में किए सबसे ज्यादा गोल

रोनाल्डो इस मैच में दो गोल करने के साथ ही पुर्तगाल के लिए फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने जैसे ही दूसरा गोल दागा और इस मामले में आगे निकल गए। रोनाल्डो ने इस मामले में यूरोपियों को पीछे छोड़ा जिन्होंने पुर्तगाल के लिए विश्व कप में नौ गोल किए हैं।

छह विश्व कप में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी

रोनाल्डो छह विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने पहली बार विश्व कप में गोल करने का कारनामा 2006 में किया था। इसके बाद उन्होंने 2010, 2014, 2018, 2022 और अब अपने छठे विश्व कप संस्करण में भी गोल कर इतिहास रच दिया। इससे पहले कोई भी पुरुष फुटबॉलर लगातार छह अलग-अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल नहीं कर पाया था।

उज्बेक खिलाड़ी ने किया आत्मघाती गोल

दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के अब्दुखोदिर खुसानोव ने आत्मघाती गोल किया जिससे पुर्तगाल 4-0 की बढ़त बनाने में सफल रहा। दरअसल, पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस ने कॉर्नर पर किक मारा और गोल पोस्ट के पास खड़े खुसानोव के कंधे से लगते ही गेंद गोल पोस्ट को पार कर गई। इसके बाद पुर्तगाल ने पांचवां गोल कर उज्बेकिस्तान के खिलाफ बढ़त को बेहद मजबूत कर लिया। पुर्तगाल के लिए पांचवां गोल राफेल लियाओ ने 87वें मिनट में किया। उज्बेकिस्तान की टीम अंत तक मैच में एक भी गोल नहीं कर सकी।

पाकिस्तान पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम का दबदबा बरकरार

एफआईएच प्रो लीग मुकाबले में दी शिकस्त

लंदन, एजेंसी

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग के मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से हराया। भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा बरकरार है और टीम 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं हारी है। इतना ही नहीं भारत पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 18 मैचों से अजेय चल रहा है और लंदन में भी टीम का दबदबा देखने मिला।

भारत ने पिछड़ने के बाद की वापसी भारत के लिए अभिषेक, निलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और रजिंदर सिंह ने एक-एक गोल दागे, जबकि पाकिस्तान की ओर से अहमद नदीम, अबु महमूद और मोहिन शकील ने गोल किए। दोनों टीमों के बीच चौथे क्वार्टर तक मुकाबला बेहद रोमांच नजर आया। पाकिस्तान ने अंतिम क्वार्टर में दो



गोल करके बढ़त कम करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम मुकाबला अपने नाम करने में सफल रही। प्रो लीग की तालिका में आखिरी स्थान पर काबिज पाकिस्तान ने आठवें मिनट में ही नदीम अहमद के गोल के दम पर बढ़त बना ली थी। इसके बाद भारत को 22वें मिनट में अभिषेक ने

बराबरी दिलाई। भारत ने बढ़त लेने में ज्यादा देर नहीं लगाई और 24वें मिनट में निलकांत ने शानदार गोल के जरिये स्कोर 2-1 कर दिया। इसके बाद सुखजीत ने 40वें मिनट में एक और गोल कर भारत की बढ़त मजबूत कर दी। अंतिम क्वार्टर में रजिंदर ने 52वें मिनट में गोल कर स्कोर 4-1 किया।

भारत का अब इंग्लैंड से सामना

भारत को अब शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड से खेलना है। भारत और पाकिस्तान 2024 में चीन के हलुनबुइर में हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले के बाद पहली बार एक-दूसरे के सामने थे जब भारत ने हरमनप्रीत सिंह के दो गोल के दम पर 2-1 से जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2016 में भारत को हराया था जब गुवाहाटी में सैफ खैलों ने भारत की दूसरे दर्जे की टीम ने भाग लिया था

हालांकि, पाकिस्तान के लिए अबु महमूद ने 53वें मिनट में गोल दागा और फिर 60वें मिनट में मोहिन ने गोल कर हार का अंतर कम कर दिया।

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के लिए वह पल आखिर आ ही गया, जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में पहली बार चुने गए 15 वर्षीय बल्लेबाज ने जब टीम इंडिया की जर्सी पर अपना नाम देखा, तो वो इमोशनल हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में अपनी भावनाएं जाहिर कीं। वैभव ने कहा कि क्रिकेट खेलने की शुरुआत ही उन्होंने उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाए। वैभव कहते हैं, वो टीशर्ट देखते ही मैं इतना खुश हो गया कि मतलब मैं स्माइल कर रहा था। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज नहीं सोचते हैं वो आपके साथ होता है।

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, इस एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल है। जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से



बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पर मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो ड्रीम मेरा आज पूरा हुआ। जो मेन स्टेप होता है, वो आज कम्प्लीट हुआ। मैं इस चीज को शब्दों में विस्तार से बता नहीं सकता। ड्रीम जैसा ही लग रहा था। युवा बल्लेबाज ने बताया कि जैसे ही उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी देखी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाए। वैभव कहते हैं, वो टीशर्ट देखते ही मैं इतना खुश हो गया कि मतलब मैं स्माइल कर रहा था। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चीज नहीं सोचते हैं वो आपके साथ होता है।

वैभव कर रहे ताबड़तोड़ प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह यू ही नहीं मिली है। पिछले एक साल में उन्होंने हर बड़े मंच पर अपने बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया है कि चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। हाल ही में इंडिया-ए की ओर से खेले हुए उन्होंने त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने महज 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी बैटर की सबसे तेज फिफ्टी रही। इससे पहले अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को वैश्वियन बनाया था।

मनोरंजन बॉलीवुड का कोना

दर्शकों के भरोसे से समझौता नहीं कर सकती थी इसलिए टुकड़ाई फिल्में, आशिकी स्टार का बड़ा खुलासा

मुंबई। 1990 की सुपरहिट फिल्म आशिकी से रातोरात स्टार बनीं पूर्व अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने अपने फिल्मी करियर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने करियर के दौरान कई फिल्मों के प्रस्ताव टुकड़ा दिए थे। अनु अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उनके लिए लोकप्रियता से ज्यादा दर्शकों का भरोसा और उनकी मेहनत की कमाई मायने रखती थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए अपने फैसलों के पीछे की सोच को विस्तार से बताया।

अनु अग्रवाल ने कहा कि एक कलाकार के रूप में उन्हें हमेशा यह बात परेशान करती थी कि लोग उनकी फिल्मों देखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं। उन्होंने लिखा कि बड़ी संख्या में दर्शक



मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, जो कई बार अपनी जरूरतों से समझौता करके टिकट खरीदते हैं। ऐसे में वह हमेशा खुद से सवाल करती थीं कि क्या दर्शकों को उनके पैसे और समय के बदले वास्तव में कुछ अच्छा मिल रहा है या नहीं। पूर्व अभिनेत्री ने बताया कि यही सोच उनके फिल्म चयन का आधार बन गई। उनके लिए सिर्फ किसी फिल्म का व्यावसायिक रूप से सफल होना पर्याप्त नहीं था, बल्कि यह भी जरूरी था कि वह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती हो। उन्होंने कहा कि कई ऐसी कहानियां उनके पास आईं, जिन्हें उन्होंने दर्शकों के हित में उचित नहीं माना। इसी वजह से उन्होंने उन फिल्मों को करने से इनकार कर दिया।

दर्शकों के प्रति महसूस करती थी जिम्मेदारी

अनु अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला केवल टाइमकास्ट होने या सही किरदार चुनने तक सीमित नहीं था। वह थिएटर में बैठे हर दर्शक के प्रति जिम्मेदारी महसूस करती थीं। उनका मानना था कि दर्शकों ने उन्हें पहचान, सम्मान और सफलता दी है, इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि वह उनके समय, भरोसे और पैसे का सम्मान करें। अनु अग्रवाल ने कहा कि यही सोच उनके पुरे करियर की पहचान रही और इसी कारण उन्होंने कई फिल्मों से दूरी बना ली। उनका यह बयान एक बार फिर इस बात को सामने लाता है कि मनोरंजन जगत में कुछ कलाकार व्यावसायिक सफलता से अधिक दर्शकों के विश्वास और गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं।



मेट्रो बाजार

बंगलुरु। इंडोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियों का स्थान नहीं लेगी, बल्कि नई तकनीक को तेजी से अपनाने वाली कंपनियों के विस्तार में मदद करेगी। कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपने संबोधन में नीलेकणी ने कहा कि बड़े उद्यम ग्राहकों में एआई के उपयोग में एक वास्तविक अंतर है, और इस अंतर को

आईटी कंपनियों को मजबूत करेगा एआई : इंडोसिस के चेयरमैन

पाटना ही हमारा लक्ष्य है। एआई हमारी जैसी कंपनियों का स्थान नहीं लेगा। यह उन कंपनियों को मजबूत करेगा, जो उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती हैं और तेजी से परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालती हैं।

उन्होंने कहा कि इंडोसिस 2030 तक 400 अरब डॉलर के एआई-आधारित सेवाओं के विशाल अवसर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है।

उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि क्या इंडोसिस जैसी कंपनियां तब भी प्रासंगिक बनी रहेंगी, जब कोडिंग का अधिकांश हिस्सा स्वचालित हो जाएगा। नीलेकणी ने कहा कि सॉफ्टवेयर

विकास केवल कोड लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन उद्यम संदर्भ, मौजूदा प्रौद्योगिकी निवेशों के साथ एकीकरण, साहजक सुझाव उपाय, परीक्षण, शासन और ऑटोमैटिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉन्च के तीन साल से अधिक समय बाद, इंडोसिस पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है और आने वाले दशक के लिए अच्छी स्थिति में है। हम सर्वश्रेष्ठ कोडिंग टूल को अपना रहे हैं और अपनी उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

सेबी का प्रस्ताव: सभी रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट कोड लाने की योजना

मुंबई। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) ने पूंजी बाजार से जुड़ी विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए एक समान विज्ञापन आचार संहिता (कॉमन एडवर्टाइजमेंट कोड - सीएससी) लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग संस्थाओं के लिए मौजूद विज्ञापन नियमों को हटकर एक एकीकृत ढांचा तैयार करना है, ताकि अनुपालन संबंधी जटिलताएं कम हों और निवेशकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके।

सेबी के प्रस्तावित नियम स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता, पोर्टफोलियो मैनेजर और म्यूचुअल फंड एवं एफंड मैनेजमेंट कंपनियों पर लागू होंगे। इस नए ढांचे को सेबी (इंटरमीडियरीज) रेगुलेशंस, 2008 में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

सेबी ने विज्ञापन जारी करने से पहले मंजूरी लेने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर पोस्ट-रिपोर्टिंग सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है। इसके तहत किसी भी विज्ञापन को जारी करने के बाद संबंधित संस्था को 24 घंटे के भीतर प्रस्ताव रखा है। इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग संस्थाओं के लिए मौजूद विज्ञापन नियमों को हटकर एक एकीकृत ढांचा तैयार करना है, ताकि अनुपालन संबंधी जटिलताएं कम हों और निवेशकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। सेबी के प्रस्तावित नियम स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता, पोर्टफोलियो मैनेजर और म्यूचुअल फंड एवं एफंड मैनेजमेंट कंपनियों पर लागू होंगे। इस नए ढांचे को सेबी (इंटरमीडियरीज) रेगुलेशंस, 2008 में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।



कॉमर्शियल सुनील पाल एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस पोस्ट को लोग अभिनेत्री आलिया भट्ट पर तंज मान रहे हैं, जिसके चलते मनोरंजन जगत में नई बहस छिड़ गई है। यह पूरा मामला कॉमर्शियल समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां हाल ही में आलिया भट्ट और अभिनेत्री शरवरी वाघ अपनी आने वाली फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं।

इस पूरे मामले को शुरुआत तब हुई जब शो के नए सीजन में समय रैना ने एक पुराने वायरल कमेंट का

जहां हैं गालियां, वहां है आलिया: सुनील पाल के पोस्ट को लोगों ने माना आलिया भट्ट पर तंज

जिक्र किया। शो के दौरान उन्होंने एक कमेंट से हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा कि वह कौन सा ट्यूटोरियल इस्तेमाल करती है। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा कि वही ट्यूटोरियल सुनील पाल को भी दे देना। यह लाइन सुनकर सेट पर मौजूद लोग हंस पड़े। इसी एपिसोड में आलिया भट्ट भी मौजूद थीं और वह भी इस पर हंसती हुई नजर आईं। बाद में आलिया ने बताया कि उन्होंने पहले वह एपिसोड देखा था, जिसमें समय रैना और सुनील पाल एक साथ %द ग्रेट



इंडियन कपिल शो% में दिखाई दिए थे। इस पर सुनील पाल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया और हिंदी में लिखा, %जहां हैं गालियां, वहां हैं आलिया।% इस पोस्ट को लोग सीधे तौर पर आलिया भट्ट पर कटाक्ष मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने यह किस संदर्भ में लिखा है। दरअसल, समय रैना ने कपिल शो के शो पर सुनील पाल से सवाल किया था- आप ब्रश क्यों नहीं करते?%



हिमाचल के जंगलों की कीमत है 22 हजार 6 सौ करोड़ रुपए

शिमला। काउंटिंग ग्रीन वेल्थ : टुवर्ड्स अ पयूचर-रेडी पीपल्स फॉरेस्ट इकोनॉमी इन हिमाचल प्रदेश नाम की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हिमाचल के जंगलों में 22,600 करोड़ रुपए की बायो-इकोनॉमी (जैव-अर्थव्यवस्था) की बड़ी छिपी हुई क्षमता है। यह कीमत इसके मौजूदा संसाधनों की दर्ज कीमत से दोगुनी से भी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और एक संस्थान द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पश्चिमी हिमालय में प्रकृति के पारंपरिक संरक्षण को एक लाभदायक और टिकाऊ बायो-इकोनॉमी में बदला जा सकता है। एक एजेंसी के मुताबिक बायो-इकोनॉमी एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो जीवाश्म-आधारित ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय भोजन, ऊर्जा, सामग्री और सेवाएं बनाने के लिए नदीकरणीय जैविक संसाधनों - जैसे फसलें, जंगल, जानवर और सूक्ष्मजीव - का उपयोग करता है। अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई इस रिपोर्ट में चार प्रमुख उद्योगों की रूपरेखा बताई गई है।

वन विभाग की रिपोर्ट में बड़ा दावा

रेजीम चेंज बुक से हुआ खुलासा

यूक्रेन युद्ध में भारतीय सेना भेजना चाहते थे जेडी वेंस

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर आई एक नई किताब में किए गए एक दावे ने वैश्विक राजनीति में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। 23 जून को रिलीज हुई किताब 'रेजीम चेंज' के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध को रोकने की रणनीति पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के विचारों को एक मुद्दे में पूरी तरह से अलग-थलग दिखाया गया है। किताब में दावा किया गया है कि ट्रंप के शपथ लेने के महज 10 दिन बाद (30 जनवरी 2025) ओवल ऑफिस में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई।

किताब में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ओवल ऑफिस में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुझाव दिया कि यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए भारत या सऊदी अरब के सैनिकों को तैनात किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने हंसते हुए इस आइडिया को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय ऐसा नहीं करेंगे। वे इस तरह की चीजों के लिए पैसे नहीं खर्च करेंगे। किताब के लेखकों के अनुसार, यह बैठक ट्रंप द्वारा यूक्रेन और रूस के लिए नियुक्त विशेष दूत, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने बुलाई थी। केलॉग ने



इस बैठक में 'एन अमेरिका फर्स्ट' प्लान: ट्रम्प हिस्टोरिक पीस डील फॉर रशिया-यूक्रेन वॉर' नाम से एक ड्राफ्ट पेश किया था। किताब के अनुसार इस शांति योजना का मुख्य बिंदु था कि यूक्रेन में तुरंत युद्धविराम (सीजफायर) लागू किया जाए। अमेरिका, यूक्रेन के उन हिस्सों पर रूस के कब्जे को आधिकारिक मान्यता नहीं देगा जिन पर उसने कब्जा किया है। बदले में यूक्रेन भी सैन्य ताकत के दम पर उन इलाकों को वापस छीने की कोशिश नहीं करेगा और इस युद्धविराम की निगरानी के लिए वहां विदेशी सैनिकों को तैनात किया जाएगा। विचारों में मतभेद की अटकलें और दावों की शुरुआत ही यहीं से होती है। कारण है कि उस समय भी वेंस नाटो सेना को इस योजना में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि केलॉग के शुरुआती प्लान में सुझाव था कि फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों के सैनिकों को यूक्रेन में शांति सेना के रूप में जमीन पर उतारा जाए।

भारत में हर साल फलू से 1.2 लाख मौतें, टीका लेने वाले 2% भी नहीं

बुजुर्गों की सेहत पर भारी पड़ रही लापरवाही

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। 'जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ गेरियाट्रिक्स' में छपे विशेषज्ञों के एक नए अध्ययन के अनुसार, देश में हर साल इम्प्यूंजा (फलू) के कारण लगभग 1.2 लाख लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इस रिपोर्ट में ज्यादा ध्यान करने वाली बात यह है कि इनमें करीब दो-तिहाई लोग 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होते हैं। इसके बाद भी देश के 2% बुजुर्गों ने भी फलू से बचाव का टीका नहीं लगवाया है।

रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने 'लॉगीट्यूइल एजिंग स्टडी इन इंडिया' के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बुजुर्गों में टीकाकरण की स्थिति बेहद दुखद है। रिपोर्ट के मुताबिक टिटनेस-डिफ्टीरिया का टीका सिर्फ 2.75% बुजुर्गों ने लगवाया है। हेपेटाइटिस बी का टीका केवल 1.82% लोगों को मिला है। इम्प्यूंजा (फलू) की वैक्सीन महज 1.59% बुजुर्गों तक पहुंची है। इतना ही नहीं चौंकाने वाली बात तो यह है कि निमोनिया से बचाने वाला न्यूमोकोकल वैक्सीन तो सिर्फ 0.74% लोगों ने ही लिया है।



निमोनिया का खतरा सबसे ज्यादा

रिपोर्ट में जहां एक तरफ इस बात पर जोर दिया गया है कि निमोनिया का टीकाकरण सबसे कम हुआ है। वहीं, दूसरी ओर रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बुजुर्गों के अस्पताल में भर्ती होने की सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है, जिसमें निमोनिया सबसे आम है। इसके बाद भी 1% से कम बुजुर्गों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन ली है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में हर साल खतरनाक न्यूमोकोकल बीमारी से 6 से 8 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग या पहले से बीमार लोग शामिल हैं। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉ. सनी सिंघल और एम्स दिल्ली, जिपमेर पुडुचेरी व सीएमसी वेतोर जैसे बड़े संस्थानों के डॉक्टरों की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उनके अनुसार, इस लापरवाही की मुख्य वजह है कि भारत में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए कोई एक तय राष्ट्रीय गाइडलाइन नहीं है।

सोनभद्र में ओबरा डैम से पानी छोड़ने से रेणुका नदी में फंसे 11 सैलानी, टाई घंटे बाद बचाया

सोनभद्र, एजेंसी

रेणुका नदी छठ घाट पर सोमवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब दिल्ली और ओबरा के 11 सैलानी अचानक बड़े जलस्तर के कारण नदी के बीच बने ऊंचे स्थान पर फंस गए। करीब ढाई घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना ने डैम से पानी छोड़े जाने की व्यवस्था और चेतावनी तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया है। ओबरा के सेक्टर-10 निवासी आदित्य, राहुल, देव और आलोक के यहां दिल्ली से उनके रिश्तेदार नीतिन, शमली, कुशल, माही, राशि, गरिमा समेत अन्य लोग आए हुए थे। सोमवार शाम सभी रेणुका नदी छठ घाट घूमने पहुंचे। नदी में पानी कम होने के कारण सभी लोग तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने के लिए नदी के बीच तक चले



गए। इसी दौरान शाम करीब छह बजे ओबरा डैम से जल विद्युत उत्पादन के लिए दो टरबाइन संचालित किए गए, जिससे नदी में लगभग 32 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी छोड़ा गया। पानी का बहाव बढ़ते ही नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर आने लगा। किनारे पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर लोगों को सतर्क किया। कुछ लोग बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन 11 सैलानी बीच धारा में फंस गए।

झूठ की बुनियाद पर न्याय पाने की कोशिश, कानूनी व्यवस्था की आत्मा पर प्रहार है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

न्याय का मंदिर माने जाने वाले कोर्ट में अगर झूठ और फरेब की बुनियाद पर न्याय पाने की कोशिश की जाए, तो यह पूरी कानूनी व्यवस्था की आत्मा पर प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक प्रक्रियाओं में जालसाजी (फोर्जरी) और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना बेहद गंभीर अपराध है और इसे किसी भी स्तर में हल्के में नहीं लिया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेज को असली के

रूप में इस्तेमाल करना) जैसे प्रविधान सरकारी और कानूनी दस्तावेजों की पवित्रता व विश्वसनीयता की रक्षा के लिए हैं। कोर्ट के सामने ऐसे जाली कागज पेश करना न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तलख टिप्पणी उस मामले को सुनवाई के दौरान की, जहां एक व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही में जमानत/गारंटी देने के लिए फर्जी राजस्व दस्तावेज इस्तेमाल करने के जुर्म में पांच साल की सजा सुनाई गई थी। पीठ ने कहा कि जहां एक तरफ अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ सजा तय करते समय आरोपित की भूमिका, जेल में बिताए गए समय और मामले की परिस्थितियों के बीच एक मानवीय संतुलन बनाना भी जरूरी है।



मेट्रो एंकर

जून माह के मासिक भंडार की सात चरणों में हुई गणना

सांवलिया सेट : 40.81 करोड़ से अधिक की नकदी का चढ़ावा

उदयपुर, एजेंसी

मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेट मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था एक बार फिर भंडार गणना में झलक उठी। जून माह के मासिक भंडार की सात चरणों में हुई गणना में मंदिर को कुल 40 करोड़ 81 लाख 40 हजार 278 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। यह राशि पिछले वर्ष जून माह की तुलना में 11 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक है, जिसने नया रिकॉर्ड कायम किया है।

ऑनलाइन चढ़ावे से हुई बड़ी प्राप्ति

मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में 33 करोड़ 15 लाख 18 हजार 759 रुपए भंडार से तथा 7 करोड़ 66 लाख 21 हजार 519 रुपए ऑनलाइन और भेंटकक्ष से प्राप्त हुए। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने 1 किलो 738 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना तथा 110 किलो 648 ग्राम चांदी भी अर्पित की।



आस्था का बढ़ता विरवास

पिछले वर्ष जून 2025 में मंदिर को 29.53 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला था। इस बार चढ़ावे में उल्लेखनीय वृद्धि को मंदिर मंडल ने श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और सांवलिया सेट के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। गणना प्रक्रिया मंदिर मंडल, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई।

त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या भीड़ ने आरोपी का घर जलाया

अगरतला, एजेंसी

पश्चिम त्रिपुरा जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बाद मंगलवार को गुस्साई भीड़ ने एक आरोपित के घर को आग लगा दी है। पुलिस ने बताया कि मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। एक स्थानीय क्लब के सचिव भी थे। उन्हें आधी रात के करीब एक आमंत्रण में शामिल होकर घर लौटते समय फावड़े से सिर पर वार करके मार दिया गया। पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक नमित पाठक ने कहा कि हत्या के संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अपराध के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमले



के पीछे के लोग भी क्षेत्र में भाजपा सदस्यों के रूप में जाने जाते थे। दास का खून से सना शव मिलने के बाद महिलाओं के एक समूह ने आरोपित के बड़े भाई के घर पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस और सीआरपीएफ के कर्मियों ने उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोका। कुछ घंटों बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने घर के बाहर इकट्ठा होकर उसे आग लगा दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।